नागरिक विविध.

डी. के. महाजन और गोपाल सिंह न्यायमूर्ति के समक्ष.

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल।–याचिकाकर्ता

बनाम।

पंजाब राज्य आदि–प्रतिवादी।

1965 की सिविल रिट संख्या 3060।

20 मई 1971.

पंजाब एक्साइज एक्ट (1914 का I) - धारा 20, 21, 36 और 41 - पंजाब डिस्टिलरी नियम (1952) - नियम 7 और फॉर्म डी–2 - फॉर्म डी – 2 में धारा 20 (2) के तहत जारी किया गया डिस्टिलरी लाइसेंस – वित्तीय आयुक्त –क्या लाइसेंस प्राप्त डिस्टिलरी को बंद करने के लिए सक्षम है – ऐसे लाइसेंस की शर्त 9 - क्या मनमाना या अनुचित – धारा 36-जी,

नियम 7 और लाइसेंस की शर्त 9 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध – क्या धारा 20 (2) और 21 (सी) के साथ असंगत हैं और (डी) – डिस्टिलरी लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस जारी करते समय वित्तीय आयुक्त – क्या अर्ध–न्यायिक तरीके से कार्य करता है – प्राकृतिक न्याय के नियम – क्या डिस्टिलरी लाइसेंस को समाप्त करने के नोटिस के मुद्दे पर लागू होता है – नियमों का अनुपालन या प्राकृतिक न्याय जब उत्पन्न होता है –भारत का संविधान (1950) -अनुच्छेद 19 और 226 -संपत्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन –क्या एक सीमित कंपनी द्वारा रिट याचिका में आग्रह किया जा सकता है –एक डिस्टिलरी लाइसेंस का निर्धारण –क्या यह लाइसेंसधारी के अधिकार का उल्लंघन करता है व्यापार।

417

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल बनाम पंजाब राज्य, आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .)

माना गया कि पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 20 और 21 को संचयी रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्राधिकारी, जो डिस्टिलरी को बंद करने में सक्षम है, जिसके संबंध में लाइसेंस दिया गया है, वित्तीय आयुक्त है। धारा 21 का खंड (बी) सामान्य तौर पर वित्तीय आयुक्त को किसी भी डिस्टिलरी को बंद करने की शक्ति प्रदान करता है जो उसके द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत स्थापित की गई है। अभिव्यक्ति 'किसी भी डिस्टिलरी को बंद करना' का तात्पर्य लाइसेंसधारक को डिस्टिलरी चलाने में सक्षम बनाने वाले वित्तीय आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के निर्धारण या रद्दीकरण से है। अधिनियम की धारा 36 में विभिन्न आधार प्रदान किए गए हैं, जिनके आधार पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। धारा 36 के खंड (जी) के तहत लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी को इसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है. वित्तीय आयुक्त द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है, यह वह है, जो धारा के खंड (जी) के तहत निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 से जुड़े फॉर्म

डी. 2 में जारी लाइसेंस की शर्त 9 के तहत, यह वित्तीय आयुक्त भी है; जो लाइसेंस निर्धारित करने में सक्षम है।

(पैरा 25, 26 और 27)

माना गया कि अधिनियम की धारा 36(जी) के प्रावधानों और फॉर्म डी में जारी लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 7 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध मनमाना या अनुचित नहीं है। अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की इच्छानुसार लाइसेंस रद्द करने की शक्ति, पूर्ण शक्ति नहीं है। यह ओवर–राइडर के अधीन है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार रद्द करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लाइसेंस की शर्तें ऐसे रद्दीकरण के लिए प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में, खंड (जी) के तहत एक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस में शामिल एक शर्त का पालन करने के लिए सहमत हो गया है कि उसका लाइसेंस उस खंड के तहत रद्द किया जा सकता है, शक्ति को मनमाने ढंग से रद्द किया जा सकता है और

अनियंत्रित, यदि अभिव्यक्ति के बाद, 'इच्छा पर', विधायिका आगे यह प्रावधान नहीं करती कि यह लाइसेंस की शर्तों के अधीन है जैसा कि लाइसेंसधारी और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत है। ऐसा प्रावधान करके, विधायिका ने इस प्रावधान से, मनमाने ढंग से काम करने वालों के दंश या निरंकुश शक्ति के प्रयोग को हटा दिया है ताकि शक्ति को इच्छानुसार प्रयोग करने और दुरुपयोग होने से बचाया जा सके।

(पैरा 53),

माना गया कि अधिनियम की धारा 36(जी), नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अधिनियम की धारा 20(2) और 21 (सी) और (डी) के साथ असंगत नहीं हैं। . धारा 36(जी) कहती है कि यदि लाइसेंसधारी सहमत है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द कर सकता है। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के संदर्भ में लाइसेंस द्वारा किए गए समझौते को उसके द्वारा अनुपालन करने के लिए अधिनियम की धारा 36 (जी) द्वारा लगाया

गया प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। यह शर्त लाइसेंस के मुख्य भाग में लाइसेंसधारी के सहमत होने के कारण मौजूद है, न कि उसकी इच्छा के विरुद्ध लगाए गए किसी प्रतिबंध के कारणः नियम 7 वित्तीय आयुक्त को लाइसेंस निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है और उसकी शक्ति पर एक बंधन लगाता है। उसके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह लाइसेंसधारी को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नोटिस देने के बाद लाइसेंस का निर्धारण करे। लाइसेंस की शर्त संख्याः 9 के साथ पढ़े जाने वाले नियमों की धारा 36 (जी) और नियम 7 का दायरा दर्शाता है कि उनके बीच कोई असंगतता नहीं है और धारा 20 (2) धारा 20 (2) लाइसेंस देने की शक्ति से संबंधित है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद ही इसके रद्दीकरण का प्रश्न उठता हैः नियम 7 और शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ी गई धारा 36(जी) के संदर्भ में। यह अनुभाग एक अलग विषय से संबंधित है और धारा 36(जी), नियम 7 और शर्त संख्या 9 द्वारा निपटाए गए विषय से स्वतंत्र है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 36(जी) और नियम 7 के बीच कोई

असंगतता नहीं है। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 और धारा 21 के खंड (सी) और (डी) के साथ पढ़े जाने वाले नियम।

418

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1973)2

(पैरा 54 और 56)

माना गया कि अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के तहत, लाइसेंस को इच्छानुसार रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेंस की शर्तें इस तरह के रद्दीकरण के लिए प्रदान करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि लाइसेंस में शामिल किसी शर्त के द्वारा, लाइसेंसिंग प्राधिकारी और लाइसेंसधारी परस्पर सहमत होते हैं कि लाइसेंस उस प्राधिकारी द्वारा बताए बिना किसी भी कारण के रद्द किया जा सकता है, तो लाइसेंस ऐसे रद्दीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर्म डी 2 में जारी लाइसेंस की शर्त संख्या 9। लाइसेंसिंग प्राधिकारी और लाइसेंसधारी द्वारा तैयार और पारस्परिक रूप से सहमत यह प्रावधान है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी

लाइसेंसधारक को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि लाइसेंस की समाप्ति पर लाइसेंस निर्धारित किया जाएगा। नोटिस की तारीख से एक वर्ष से कम। लाइसेंस की इस शर्त से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जैसा कि लाइसेंसधारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लाइसेंस बिना किसी कारण के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि धारा 36 के खंड (जी) द्वारा विचार किया गया है, जिसके अनुसरण में यह शर्त डाली और स्वीकार की गई है लाइसेंसधारी द्वारा संविदात्मक दायित्व के रूप में। लाइसेंस के निर्धारण की शर्त के साथ जोड़ी गई एकमात्र सीमा यह है कि लाइसेंस के निर्धारण के लिए जारी नोटिस की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए लाइसेंस के अनुबंध की शर्त 9 के तहत नोटिस जारी करने का मामला, जिसके तहत इसे समाप्त किया जा सकता है, पूरी तरह से एक प्रशासनिक अधिनियम है और ऐसा करने वाला प्राधिकारी प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है, न कि अर्ध–न्यायिक क्षमता में।

(पैरा 32)

माना गया कि लाइसेंस की शर्त संख्या 9 की प्रकृति और लाइसेंसधारी को सुनने के लिए नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी पर वैधानिक या अन्यथा किसी भी दायित्व की इच्छा पर विचार करते हुए, प्राधिकारी पूरी तरह से प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है। लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए उसे किसी सबूत पर विचार नहीं करना होगा। इसमें केवल शर्त संख्या, 9 को देखना है और लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस देना है। लाइसेंसधारी का सुनवाई का अधिकार और उसके बचाव में विचार किया जाना उस शर्त की सामग्री से अलग है। शर्त के दायरे के अनुसार नोटिस जारी करना या न जारी करना पूरी तरह से वित्तीय आयुक्त के विवेक पर निर्भर है। उस स्थिति में कार्यवाही करते समय किसी भी विवाद पर कोई निर्णय नहीं देना होगा। अनुबंध की उस अवधि के तहत कार्रवाई करते समय वित्तीय आयुक्त की शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। शर्त 9 के साथ लाइसेंस लाइसेंस को एक डिस्टिलरी में काम करने की अनुमति मात्र बना देता है, बशर्ते लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसकी समाप्ति

के लिए एक वर्ष का नोटिस दे। यह शर्त लाइसेंस को डिस्टिलरी में काम करने के लिए दिया गया एक विशेषाधिकार बनाती है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसमें दिए गए नोटिस के अनुसार किसी भी समय लाइसेंस वापस लेने का अधिकार और शक्ति अपने पास रखता है। इसलिए प्राकृतिक न्याय के नियम किसी डिस्टिलरी लाइसेंस को समाप्त करने के नोटिस के मुद्दे पर लागू नहीं होते हैं।

(पैरा 34 और 35)

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल बनाम पंजाब राज्य, आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .)

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल बनाम पंजाब राज्य, आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .)

माना गया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुपालन का प्रश्न तभी उठता है जब वैधानिक प्रावधानों में यह संकेत हो कि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की जाती है। प्राकृतिक न्याय के नियम लागू

नहीं होते हैं और उनकी प्रयोज्यता तब तक आकर्षित नहीं की जा सकती जब तक कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान उन्हें लागू करने की आवश्यकता की दिशा में इंगित न करें। यह सच है कि यदि किसी वैधानिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालय को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधायिका और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। लेकिन, दूसरी ओर, यदि कोई वैधानिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के किसी या सभी नियमों या सिद्धांतों के आवेदन को बाहर करता है, तो न्यायालय विधायिका या वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसमें पढ़ सकता है। संबंधित प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं, यह शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान के स्पष्ट शब्दों, प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है और पर निर्भर करता है। उस शक्ति के प्रयोग का प्रभाव.

(पैरा 40)

माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के खंड (ए) से (जी) में निहित मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल नागरिकों को दी गई है। नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्ति उन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड कंपनी एक निगमित निकाय होने के नाते और नागरिक नहीं होने के कारण अपने उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करते हुए रिट याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार केवल नागरिकों को है, निगमित निकायों को नहीं। किसी सीमित कंपनी के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप–खंड (एफ) या उप–खंड–ई (जी) के उल्लंघन के आधार पर अपना दावा करना संभव नहीं है।

(पैरा 42 और 43)

माना गया कि भारत का कोई भी नागरिक शराब का निर्माण या बिक्री करने की कोई स्वतंत्रता या अधिकार रखने का दावा नहीं कर

सकता है। इस उद्देश्य के लिए दिया गया लाइसेंस उसकी शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों से घिरा होता है, जिसके अनुपालन के लिए लाइसेंसधारी खुद को उन शर्तों और प्रावधानों से बांधता है, शराब बनाने का उसका अधिकार, यदि इसे अधिकार कहा जा सकता है बिल्कुल भी, लाइसेंस की शर्तों के तहत समाप्ति के लिए उत्तरदायी है। शराब जैसी वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंस की प्रासंगिक शर्तों के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध उचित प्रतिबंध हैं और आम जनता के हित में हैं। इसलिए किसी डिस्टिलरी लाइसेंस का उसकी शर्त के अनुसार निर्धारण, लाइसेंसधारी के व्यवसाय जारी रखने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 46)

16 मई को माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित द्वारा मामले को खंडपीठ को भेजा गया। 1966, मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए। मामले का निर्णय अंततः 20 मई, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति गोपाल सिंह की खंडपीठ द्वारा किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को उचित रिट द्वारा कंपनी के शराब के आसवन और निर्माण के व्यवसाय को संचालित करने और जारी रखने के अधिकार में 21 दिसंबर, 1965 और उसके बाद हस्तक्षेप करने से रोका जाए, और 14 दिसंबर, 1964 के नोटिस में यह भी कहा गया कि डिस्टिलरी को बंद कर दिया जाएगा और 21 दिसंबर, 1965 के बाद इसके वर्तमान परिसर में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और फॉर्म डी. 2 में लाइसेंस भी 21 दिसंबर, 1965 से निर्धारित किया जाएगा। , को उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की क्षमता से परे अवैध अप्रवर्तनीय होने के कारण रद्द कर दिया जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि याचिका का निर्णय लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और याचिकाकर्ता कंपनी को करनाल में मौजूदा लाइसेंस प्राप्त परिसर में अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाए। प्रतिवादियों

को निर्देश दिया जाए कि वे लाइसेंस का निर्धारण करने या उसे रद्द करने से बचें।

याचिकाकर्ता के लिए एम. एल. सेठी, डी. एन. ए. वास्थी, वरिष्ठ वकील ए. के. जयसवाल और ए. सी. जैन, ए वकील।

उत्तरदाताओं के लिए डी. एस. नेहरा, और के. एस. नेहरा, वकील।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गयाः–

गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .–यह करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल द्वारा पंजाब राज्य अब हरियाणा राज्य और वित्तीय आयुक्त और उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, पंजाब अब हरियाणा के खिलाफ एक रिट याचिका है, जिसमें क्रमशः पंजाब अब हरियाणा राज्य को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने 14 दिसंबर 1964 के नोटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता–कंपनी को एक वर्ष की अवधि

की समाप्ति के बाद 21 दिसंबर 1965 को अपना लाइसेंस निर्धारित करने के लिए भेजा था। पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 21 (बी) के तहत नोटिस की तामील की तारीख, इसके तहत बनाए गए पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 7 (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) और शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ा जाएगा। अधिनियम की धारा 20(2) के तहत जारी लाइसेंस। उठाए गए सवालों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मामले को पंडित, जे. ने एक डिवीजन बेंच को भेज दिया है।

(2) रिट याचिका से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैंः –

421

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल बनाम पंजाब राज्य, आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .)

(3) याचिकाकर्ता–कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी है। इसके प्रबंध निदेशक श्री

एस.पी.जायसवाल हैं। श्री एस. पी. जयसवाल के पिता श्री किशोरी लाई जयसवाल ने 1903 में करनाल शहर में उस स्थान पर डिस्टिलरी स्थापित की थी जहां अब यह काम कर रहा है। श्री किशोरी लाई जायसवाल की 1928 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद से उनके बेटे याचिकाकर्ता–कंपनी के नाम से डिस्टिलरी चला रहे हैं। उस इलाके के निवासियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, जहां डिस्टिलरी स्थित है, 1939 में करनाल की नगर समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि डिस्टिलरी, जो करनाल शहर के केंद्र में स्थित थी, उपद्रव करने वाली थी। उस इलाके के निवासी, जहां यह स्थित था और स्वच्छता के आधार पर शहर में डिस्टिलरी को जारी रखना वांछनीय नहीं था और इसे किसी अन्य दूर और उपयुक्त स्थान पर हटा दिया जाना चाहिए। 1939 में, याचिकाकर्ता–कंपनी को डिस्टिलरी को करनाल शहर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कई वर्षों की लंबी अवधि का नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता–कंपनी को एक नोटिस भी दिया गया था कि यदि वह डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के निर्देश का

पालन करने में विफल रही, तो उसका लाइसेंस निर्धारित किया जाएगा। याचिकाकर्ता–कंपनी को 5 नवंबर, 1941 को अधिनियम की धारा 20(2) के तहत फॉर्म डी–2 में एक नया लाइसेंस प्रदान किया गया था, जिसे अब नोटिस में रद्द करने की मांग की गई है। कंपनी को दी गई समयावधि के भीतर डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने में विफल रहने पर, कंपनी को उत्तरदाताओं की ओर से याचिकाकर्ता को संबोधित पत्र दिनांक 5 नवंबर, 1947 द्वारा फिर से स्थानांतरित करने के लिए तीन साल की अवधि दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तीन वर्ष की अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया गया।

(4) याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त, अंबाला को संबोधित पत्र दिनांक 21 जनवरी 1949 द्वारा, यह सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रबंधन को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए। करनाल की नगर निगम सीमा के बाहर डिस्टिलरी के लिए कुछ उपयुक्त साइट का सुझाव दिया जाना चाहिए और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि पहले से जारी लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस 30 सितंबर, 1950 को

समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता–कंपनी ने एक साइट का प्रस्ताव दिया था लेकिन यह नहीं था कलेक्टर, करनाल द्वारा अनुमोदित नहीं। कंपनी को सूचित किया गया था कि अनुमोदन के लिए चयनित साइट करनाल की नगरपालिका सीमा से 10 मील दूर आईकास्ट पर होनी चाहिए और एक होनी चाहिए, जो। निकट भविष्य में आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित होने की संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता–सीबीएमपीनी की ओर से प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए एक सुझाव के जवाब में, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी को 18 सितंबर, 1952 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक निजी उद्देश्य के लिए और याचिकाकर्ता–कंपनी को स्वयं इस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदनी चाहिए। यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता–कंपनी ने उपयुक्त साइट या अनुमोदन उपलब्ध नहीं कराया था, प्रतिवादी नंबर 3 ने 7 मार्च 1955 को पत्र द्वारा उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त को सूचित किया कि याचिकाकर्ता–कंपनी को 16 नवंबर, 1 और 35 तक डिस्टिलरी को

स्थानांतरित कर देना चाहिए। कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता–कंपनी ने उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, प्रतिवादी नंबर 3 ने 23 जून, 1956 को अन्य पत्र में सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता–: कंपनी को डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के लिए एक नई साइट खरीदनी चाहिए। काम! और वहां स्थापित होने वाली फैक्ट्री के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

(5) 1958 में, वहां एक प्रश्न पूछा गया था जिसका नाम .यूनी था। चौधरी धर्म सिंह, एम–एल.ए. द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 348। पंजाब विधान सभा के भूतल पर यह पूछा गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी की डिस्टिलरी को शहर के मध्य से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जबकि जनता और विशेष रूप से इलाके के निवासियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था। , जिसमें यह था। काम किया जा रहा है, 12 दिसंबर, 1958 को एक पत्र प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा उप सचिव, राजस्व को संबोधित

किया गया था जिसमें बताया गया था कि 'शहर के केंद्र में याचिकाकर्ता–कंपनी की डिस्टिलरी का अस्तित्व जनता के लिए एक उपद्रव था और परिणामस्वरूप डिस्टिलरी को किसी ■ उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता–कंपनी को नोटिस जारी करना पड़ा और वह। मामले की नए सिरे से जांच की जाएः

(6) फरवरी 2, 1959 के संकल्प द्वारा, एसेहबली द्वारा यह निर्णय लिया गया कि (आसवनी सीएफ •.याचिकाकर्ता–कंपनी– 'एक उपद्रव थी और उसे वर्तमान साइट से स्थानांतरित कर दिया गया था। के उत्तर में प्रतिवादी क्रमांक 3 के पत्र के अनुसार, उप सचिव ने दिनांक 25 फरवरी 1959 के पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 को सूचित किया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आसवनी को उसके वर्तमान स्थल पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कार्रवाई की मांग की गई। अप्रैल, 1959 में, विधानसभा में फिर से एक सवाल उठाया गया कि करनाल शहर से डिस्टिलरी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है और डिस्टिलरी को हटाने की मांग की गई,• बिना और देरी। डिस्टिलरी

इंस्पेक्टर, करनाल के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 3 ने 5 मई, 1959 को पत्र के साथ लाइसेंस की शर्त नंबर 9 के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत नोटिस दिया, जिसमें कहा गया था कि लाइसेंस मई को निर्धारित किया जाएगा। 15, 1960. डिस्टिलरी को अपनी साइट से स्थानांतरित करने के नोटिस का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी ने 26 मई, 1959 को पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को पूछताछ के माध्यम से निम्नानुसार लिखाः –

और हमें बताएं कि क्या सिनेट से संबंधित शर्तों को माफ कर दिया गया है या वे अभी भी कायम हैं।"

(1) विकसित होने वाले संभावित आवासीय क्षेत्र से उपयुक्त दूरी। भविष्य में, और

(2) धुले हुए कपड़ों का स्वच्छ निपटान।

(7) उस पत्र के उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 3 ने 4 जुलाई 1959 को पत्र द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी को सूचित किया कि उपरोक्त शर्तों को माफ नहीं किया जा सकता है।

(8) याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के जवाब में कि राठधना में 18 एकड़ का क्षेत्र मौजूद था, जिस पर याचिकाकर्ता–कंपनी डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार थी, प्रतिवादी संख्या 3. ने 18 अगस्त, 1959 को पत्र द्वारा संबोधित किया। उप–उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को याचिकाकर्ता–कंपनी को भेजी गई प्रतिलिपि के साथ सूचित किया गया कि विभाग एक विशिष्ट साइट के संकेत के बाद उपयुक्तता के बारे में अपनी राय दे सकता है। इसके बाद उप सचिव का एक पत्र आया कि यदि राठधाना में याचिकाकर्ता–कंपनी की डिस्टिलरी के लिए उसकी ओर से प्रतिनिधित्व की गई 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी लागत रु। याचिकाकर्ता–कंपनी को यह राशि 2,76,000 रुपये जमा करानी होगी अन्यथा याचिकाकर्ता–

कंपनी निजी बातचीत द्वारा भूमि खरीदने की व्यवस्था कर सकती है। दिनांक 28 जुलाई, 1960 को पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता ने उप सचिव को सूचित किया कि रेलवे स्टेशन, राठधना पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, याचिकाकर्ता–कंपनी को सरकारी या रेलवे खर्च पर रेलवे साइडिंग प्रदान की जाए, कंपनी को वहां नई डिस्टिलरी के निर्माण के लिए उचित समय दिया जाए, जिसकी कीमत रु. याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा 2,76,000 रुपये जमा करने की मांग की गई। 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बहुत अधिक था और जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना था उसे 200 एकड़ से बढ़ाकर 400 एकड़ किया जाना था। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 13 अगस्त, 1960 को उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को संबोधित पत्र भेजा गया, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता–कंपनी को दी गई, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी के लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है। 15 मई, 1960 को दी गई अधिसूचना को 25 जनवरी, 1961 तक बढ़ाया जाए ताकि कंपनी उस तारीख तक

डिस्टिलरी को स्थानांतरित कर सके। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से याचिकाकर्ता–कंपनी को एक और संचार दिया गया, जिसमें बताया गया कि 25 जनवरी, 1961 को डिस्टिलरी के लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया था। 17 मई, 1961 को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी को संबोधित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी से पूछा गया कि क्या कंपनी रेलवे साइडिंग के लिए खर्च वहन करने और खर्च की जाने वाली राशि का एक हिस्सा जमा करने के लिए तैयार है। इस बीच पूछताछ में रेलवे ने रेलवे साइडिंग के निर्माण का खर्च वहन करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने जवाब में 19 मई 1961 को पत्र लिखकर कहा कि कंपनी रेलवे साइडिंग के निर्माण का खर्च वहन करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे द्वारा पूरा किया जाए और याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जाए। 28 अक्टूबर, 1961 के पत्र द्वारा, उप सचिव ने याचिकाकर्ता–कंपनी को सूचित किया कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। और उसके बाद याचिकाकर्ता–

कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया और कंपनी को बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा देनी थी या नकद में जमा करना था और कंपनी को सूचित करना चाहिए कि क्या उसके लिए बैंक गारंटी देना या बनाना सुविधाजनक होगा। नकद जमा करें. यह जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी के ऐसा करने में विफलता के मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 भूमि अधिग्रहण के लिए याचिकाकर्ता कंपनी को सहायता प्रदान करने में असमर्थ होगा।

(9) करनाल की नगरपालिका समिति द्वारा पंजाब के राज्यपाल को उस इलाके के निवासियों के लिए परेशानी के आधार पर करनाल शहर से डिस्टिलरी को हटाने के लिए एक ज्ञापन दिया गया था, जहां डिस्टिलरी का काम किया जा रहा था। . रिपोर्ट के लिए प्रतिनिधित्व को पंजाब के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेजा गया था। 16 जनवरी, 1962 को पत्र दिनांक द्वारा, निदेशक ने अभ्यावेदन के संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 3 को लिखा कि डिस्टिलरी से निकलने वाली अप्रिय गंध और घृणित गंध के कारण एक उपद्रव था और परिणामस्वरूप करनाल शहर में वर्तमान स्थल पर रु। यह आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

था और इसलिए इसे उस स्थान से हटाना आवश्यक था। 3 नवंबर, 1962 के पत्र द्वारा, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि शराबबंदी के चरणबद्ध कार्यक्रम पर काम होने तक डिस्टिलरी का स्थानांतरण स्थगित रखा गया था।

(10) याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को 23 फरवरी 1963 को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि रुपये का चेक। जैसा कि पहले अवसर पर बाद वाले ने चाहा था, रक्षा निधि के लिए 5,000 रुपये भेजे जा रहे थे। उपरोक्त पत्र के उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 2 ने रुपये के चेक की प्राप्ति स्वीकार की। 5,000 और उसे बताया कि शेष राशि रु। सहमति के अनुसार 5,000 रुपये का भुगतान भी किया जा सकता है। 14 मार्च, 1963 के पत्र द्वारा, प्रतिवादी नंबर 3 के निजी सहायक द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रबंध निदेशक को एक अनुस्मारक जारी किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि रुपये की दान की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए। 5,000 शीघ्र किया जाए. इस अनुस्मारक के बाद अप्रैल, 1963 को प्रबंध निदेशक को

एक और अनुस्मारक दिया गया, जिसे निजी सहायक ने प्रतिवादी संख्या 3 को फिर से भेजा, जिसमें प्राप्तकर्ता को रुपये की शेष राशि के शीघ्र भुगतान की आवश्यकता बताई गई। 5,000. प्रबंध निदेशक ने प्रतिवादी संख्या 2 को संबोधित पत्र दिनांक 11 मई 1963 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध याचिकाकर्ता–कंपनी को गुड़ का कम कोटा आवंटित करने की शिकायत की। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने मई आईटी, 1963 के एक अन्य पत्र में प्रतिवादी नंबर 3 के निजी सहायक को संबोधित किया, जिसमें बताया गया कि डब्ल्यूएस नॉट में उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के प्रमुख द्वारा शिष्टाचार की कमी दिखाई गई थी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें लिखा था। और यह कि उनकी ओर से सम्मान की कमी के कारण, याचिकाकर्ता–कंपनी किसी भी कारण से दान के माध्यम से विभाग के माध्यम से कोई भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होगी।

(11) याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा संबोधित दिनांक 19 अगस्त, 1963 के पत्र द्वारा, यह सूचित किया गया था कि लाइसेंस के निर्धारण के लिए अंतिम नोटिस, जिसे स्थगित रखा गया था, को

पुनर्जीवित किया गया था और याचिकाकर्ता–कंपनी को ऐसा करना चाहिए। 31 मार्च, 1964 तक स्थानांतरण, ऐसा न करने पर लाइसेंस 1 अप्रैल, 1964 से प्रभावी माना जाएगा। 14 नवंबर, 1963 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 2 को सूचित किया कि वह भूमि की कीमत के भुगतान की व्यवस्था कर रही है। अधिग्रहण की मांग की गई, कि याचिकाकर्ता–कंपनी बैंक की अपेक्षित गारंटी के लिए भी व्यवस्था कर रही थी, फिलहाल याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा पहले से खरीदी गई 18J एकड़ भूमि के अलावा केवल 60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक है। , कि डिस्टिलरी करनाल से स्थानांतरित होने के 4 या 5 महीने के भीतर काम करना शुरू कर देगी और इस बीच डिस्टिलरी को अपनी वर्तमान साइट पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से प्रतिवादी नंबर 2 को संबोधित पत्र दिनांक 18 नवंबर, 1963 द्वारा, यह सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता–कंपनी रुपये की तत्काल बैंक गारंटी देने को तैयार है। अधिग्रहित की जाने वाली 60 एकड़ भूमि की कीमत के लिए 50,000

रुपये और उस क्षेत्र से अधिक भूमि के अधिग्रहण के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था 6 महीने के भीतर की जाएगी, कंपनी तारीख के 60 दिनों के भीतर नई डिस्टिलरी का निर्माण कार्य शुरू करने का वचन देती है। उन्हें अधिग्रहीत भूमि का कब्ज़ा प्रदान किया जाएगा, कि स्थापित की जाने वाली फैक्ट्री की इमारत 12 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और संयंत्र और मशीनरी रेलवे की तारीख से 60 दिनों के भीतर स्थापित हो जाएगी। साइडिंग का निर्माण रेलवे द्वारा किया गया है।

(12) 5 जून, 1963 से नवम्बर, 1963 तक याची–कम्पनी पर रुपये का जुर्माना लगाया गया। याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के आधार पर प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 17,000 रु. याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा 1964 की सिविल रिट संख्या 232, 235, 326 और 2212 से 2214 दायर की गई थी, जिसमें जुर्माना लगाने के आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। इन सभी आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि कथित अनियमितताएं अधिनियम की धारा 36 के खंड (ए) से (एफ) के दायरे में आती थीं और याचिकाकर्ता–कंपनी

को उन आदेशों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया था। , आदेश कानून की नजर में खराब थे और रद्द कर दिए गए। 1964 की सिविल रिट संख्या 315 में जुर्माना लगाने के आदेश को वैध आदेश माना गया था, लेकिन जुर्माने की वसूली से संबंधित कार्यवाही को अमान्य माना गया था।

(13) याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसरण में–; याचिकाकर्ता–कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1964 द्वारा उप सचिव से रुपये का चेक अग्रेषित किया। अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की कीमत के भुगतान हेतु जमा राशि के लिए कलेक्टर, रोहतक को 50,000 रु. फिर, 13 अगस्त, 1964 को उप सचिव की ओर से याचिकाकर्ता–कंपनी को पत्र दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता–कंपनी को सूचित किया गया कि राठधना गांव में 60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और याचिकाकर्ता–कंपनी को एक अंडरटेकिंग देनी है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह अधिग्रहीत भूमि की कीमत के लिए कलेक्टर द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का पालन करेगा।

(14) 19 मार्च 1964 को उच्च न्यायालय में 1964 की सिविल रिट संख्या 472 दायर की गई थी, जिसमें 19 अगस्त 1963 के नोटिस की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अन्य बातों के साथ–साथ नोटिस की अवधि कम है। एक वर्ष; नोटिस अमान्य था और परिणामस्वरूप लाइसेंस निर्धारित नहीं किया जा सका।

(15) इसके बाद, 14 अप्रैल, 1964 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत पंजाब राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई जिसमें सूचित किया गया कि गांव राठधाना में 60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। वह अधिसूचना पंजाब सरकार, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के सचिव श्री बी.एस. ग्रेवाल के हस्ताक्षर से प्रकाशित की गई थी। इसके मद्देनजर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित धारा 6 के तहत 14 अप्रैल, 1964 को एक और अधिसूचना जारी की गई, जिसमें इन धाराओं में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के अधिग्रहण और कब्जे की मांग की गई थी।

(16) 1964 के सिविल रिट संख्या 472 में दिए गए 26 अक्टूबर 1964 के फैसले के अनुसार, फाल्शॉ, सी.जे. और ग्रोवर न्यायमूर्ति . ने माना कि 19 अगस्त 1963 का नोटिस याचिकाकर्ता–कंपनी को लाइसेंस की शर्त 9 के तहत दिया गया था। एक वर्ष से कम की अवधि अमान्य थी और उसे रद्द कर दिया गया।

(17) उप सचिव ने 29 अक्टूबर 1964 को एक आदेश दर्ज किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 2 और उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के मंत्री के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि करनाल डिस्टिलरी को करनाल से स्थानांतरित कर दिया जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की ओर से किसी भी बाध्यता के बिना बाहरी क्षेत्र, कि इसे वहां से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक नोटिस दिया जाए, कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी जाए और सरकार को प्रबंध निदेशक को सभी उचित सहायता देनी चाहिए कंपनी उसे डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगी। उप सचिव ने 6 नवंबर, 1964 को पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित किया कि

याचिकाकर्ता–कंपनी को डिस्टिलरी को करपाल से किसी अन्य स्थान पर बिना किसी दायित्व के स्थानांतरित करने के लिए एक नया और स्पष्ट एक वर्ष का नोटिस दिया जाए। सरकार कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण करेगी. इसके बाद 14 दिसंबर, 1964 को याचिकाकर्ता–कंपनी को विवादित नोटिस भेजा गया। उस नोटिस से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता–कंपनी ने 20 दिसंबर, 1965 को एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख से पहले। याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका में यह दलील दी गई है कि लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस देने वाला प्राधिकारी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लाइसेंस का निर्धारण करने वाला नोटिस अस्पष्ट है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और पूर्ववर्ती शर्त है लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ याचिकाकर्ता कंपनी को दिए गए उचित अवसर का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि यह आदेश अर्धन्यायिक क्षमता में काम करने वाले एक प्राधिकारी द्वारा दिया गया था, जिससे आदेश ने संपत्ति में याचिकाकर्ता के अधिकारों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। कैरी बीएन बिजनेस, कि

अधिनियम की धारा 36(जी) और लाइसेंस की शर्तें संख्या 7 और 9 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मनमाने और अनुचित हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(एल)(एफ) और (जी) का उल्लंघन हैं। अधिनियम की धारा 36 और 41 के तहत लाइसेंस को रद्द नहीं किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द करने की शक्ति का प्रयोग वास्तविक नहीं है और इसका प्रयोग अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि एक संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया है। . उत्तरदाताओं की ओर से दायर अपने रिटर्न में, यह दलील दी गई कि रिट याचिका सक्षम नहीं थी क्योंकि लाइसेंस रद्द करने का निर्णय चरित्र में प्रशासनिक और विवेकाधीन था और इसलिए रिट कार्यवाही में चुनौती देने योग्य नहीं था, जिसके लिए नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी लाइसेंस रद्द करने का अधिकार उसे रद्द करने का था, कि लाइसेंस रद्द करने का निर्णय बिल्कुल भी अर्ध-न्यायिक प्रकृति का नहीं था और उत्तरदाताओं की ओर से पहले कारण बताने के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी, टीपी सेवा लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस, कि दिया गया नोटिस अस्पष्ट नहीं है

और एक वैध नोटिस है, यह देखते हुए कि अधिनियम शराब के निर्माण और बिक्री का नियामक है, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में विधायिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इसके तहत लगाए गए आरोप न तो संविधान के अनुच्छेद 19(एल)(एफ) और न ही 19(1,)(जी) का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता–कंपनी शर्तों के तहत शराब के निर्माण का व्यवसाय कर सकती है। लाइसेंस, यदि उन वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में जारी किया जाता है, तो शर्तें, जिनके अधिकार को चुनौती दी गई थी, अधिनियम की धारा 20(2) और 22(सी) और (डी) के दायरे में थीं, कि। यह दलील कि अधिनियम की धारा 36 और 41 के अलावा लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता, गलत धारणा थी, रद्द करने का नोटिस कानून के अनुसार था और रद्द करने की शक्ति का प्रयोग वास्तविक तरीके से और उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए यह किया गया था। व्यायाम करने के लिए था. उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी का आचरण ईमानदार नहीं था क्योंकि कंपनी उस साइट पर कब्जा करने पर अड़ी रही, जहां से अपनी

साइट की व्यवस्था करके स्थानांतरित करना उसकी ओर से अनिवार्य था, कि कंपनी टाल–मटोल की रणनीति से समय प्राप्त करता रहा और इस प्रकार करनाल शहर के मध्य में उस स्थान पर काम करता रहा, जिसकी स्थिति उसके इलाके के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है*।

(18)) उपरोक्त संदर्भित पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां या तो पक्षों द्वारा बहस शुरू होने से पहले दायर की गई थीं या मूल की प्रतियां अदालत में पेश की गई आधिकारिक फाइलों का हिस्सा थीं और मामले से संबंधित थीं। या तो न्यायालय के कहने पर या उनके द्वारा आपसी सहमति से वकील को दी गई अनुमति पर रिकॉर्ड करें। याचिकाकर्ता–कंपनी को नोटिस दिए जाने और इसकी वैधता को चुनौती देने वाली रिट–याचिका दायर किए जाने के बाद पार्टियों के बीच पत्राचार के क्रम में कुछ पत्र दायर किए गए हैं। ये पत्र उत्तरदाताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आग्रह की दलील को मजबूत करने के लिए दायर किए गए हैं। यह मानते हुए कि ये पत्र उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावना के

अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण या प्रासंगिक नहीं हैं, जो उन्हें पेटिर टाइनर–कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए विवादित नोटिस देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन में विज्ञापित किया गया है। अपनाए गए इस पाठ्यक्रम या मामले में शामिल बिंदुओं के निर्धारण पर एक पक्ष या दूसरे पक्ष पर होने वाले पूर्वाग्रह की आपत्ति को उठाने से बचने के लिए, वकील की आपसी सहमति के बाद बाद में दायर पत्रों की प्रतियां रिकॉर्ड पर ले ली गईं। दोनों पक्षों के लिए आगे आ रहा था.

(19) याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा अपनी याचिका एमडी में उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई दलीलों ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को जन्म दिया।

(1) जिस प्राधिकारी ने विवादित नोटिस जारी किया था, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था।

(2) याचिकाकर्ता–कंपनी को इसके निर्धारण के विरुद्ध कारण बताने के लिए नोटिस के अभाव में लाइसेंस का निर्धारण नहीं किया जा

सका। लाइसेंस रद्द करने के लिए जारी किया गया नोटिस प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है और कोई मौखिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

(3) लाइसेंस रद्द करने से याचिकाकर्ता–कंपनी की संपत्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं और यह अनुच्छेद '19(1) (एफ) का उल्लंघन है और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।) संविधान का. अधिनियम की धारा 36(जी), नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मनमाने और अनुचित प्रतिबंध हैं और धारा 20(2) और 21(सी) और (डी) के साथ असंगत हैं। अधिनियम।

(4) अधिनियम की धारा 36 और 41 के अलावा लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है।

(5) किसी भी मामले में, लाइसेंस रद्द करने की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से और संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया है, जिससे लाइसेंस रद्द करना शून्य हो गया है।

(20) याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से बिंदु संख्या 1 पर तर्क और आंशिक रूप से बिंदु संख्या 2 पर श्री एम.एल. सेठी द्वारा तर्क दिए गए और श्री डी.एन.अवस्थी द्वारा बिंदु 2 से 5 पर तर्क दिए गए, श्री नेहरा ने अदालत को संबोधित किया। उत्तरदाताओं

(21) योग्यता के बारे में पहला बिंदु निर्धारित करने के लिए। लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी करने के हकदार प्राधिकारी के लिए, हमें पहले नोटिस जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को ठीक करना होगा और फिर यह निर्धारित करना होगा कि नोटिस जारी करने वाला व्यक्ति उस प्राधिकारी का पद संभाल रहा था या नहीं। अधिनियम की धारा 20(2) के तहत याचिकाकर्ता–कंपनी को फॉर्म डी. 2 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसे वित्तीय आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी किया

गया था. यह वह लाइसेंस है, जिसे 14 दिसंबर, 1964 के विवादित नोटिस द्वारा रद्द करने की मांग की गई है। विवादित नोटिस इस प्रकार हैः –

"पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 21 (बीएफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 7 और 5 नवंबर, 1941 के लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पठित फॉर्म डी में जारी किया गया। –2 करनाल शहर में स्थित करनाल डिस्टिलरी के रूप में जाने जाने वाले परिसर के लिए करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल के पक्ष में उक्त नियमों में संलग्न, मैं, एस. सी. छाबड़ा, उत्पाद शुल्क आयुक्त, पंजाब, वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 3779-ईटी(वीएल)–64/3583, दिनांक 23 मई, 1964, कृपया सूचित करें कि उपरोक्त लाइसेंस 21 दिसंबर, 1965 (इक्कीस दिसंबर, एक हजार नौ) को निर्धारित किया जाएगा। सौ पैंसठ) जब तक कि इसे उपरोक्त नियमों

के नियम 7 के तहत इसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए पहले रद्द नहीं किया गया हो।

(22) वित्तीय आयुक्त के रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. सी. छाबड़ा द्वारा लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया है। उसे उस क्षमता में ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले प्रासंगिक प्रावधान और लाइसेंस की शर्तें इसके बाद निर्धारित की गई हैं।

(23) अधिनियम की धारा 20(2) लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करती है। वह प्रावधान इस प्रकार चलता हैः–

"धारा 21 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन प्राधिकरण के अलावा किसी भी डिस्टिलरी या शराब की भठ्ठी का निर्माण या काम नहीं किया जाएगा।" ए । ___

(24) धारा 20(2) की भाषा के अनुसार, किसी डिस्टिलरी या शराब की भठ्ठी के निर्माण और उसके कामकाज के खिलाफ व्यापक निषेध प्रदान किया गया है जब तक कि वित्तीय आयुक्त ने लाइसेंसधारी को डिस्टिलरी के निर्माण और काम करने के लिए अधिकृत करने वाला

लाइसेंस नहीं दिया हो या शराब की भठ्ठी लाइसेंस में दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन है। यह वित्तीय आयुक्त के अधिकार के तहत जारी किया गया लाइसेंस है जो लाइसेंसधारी को डिस्टिलरी का निर्माण और काम करने में सक्षम बनाता है। धारा 20 की उपधारा (2) को धारा 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 21 के तहत, वित्तीय आयुक्त को न केवल डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है, बल्कि किसी भी डिस्टिलरी को बंद करने का भी अधिकार है। जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और उसके संबंध में नियम बनाना है। अधिनियम की धारा 21 के प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: –

"वित्तीय आयुक्त, ऐसे प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन, जो राज्य सरकार लगा सकती है, ----

(ए) एक डिस्टिलरी स्थापित करें, जिसमें धारा 20 के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत स्पिरिट का निर्माण किया जा सके।

(बी) इस प्रकार स्थापित किसी भी डिस्टिलरी को बंद कर देगा।

(सी) किसी डिस्टिलरी या शराब की भठ्ठी के निर्माण और कामकाज का लाइसेंस।

(डी) इसके संबंध में नियम बनाएं–

(I) डिस्टिलरीज़, स्टिल या ब्रुअरीज के लिए लाइसेंस देना;

(3) वह अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा;

(9) पास की स्पिरिट और सामग्री का निर्माण, भंडारण और वितरण;

(11) डिस्टिलरीज़ या ब्रुअरीज के कामकाज से जुड़ा कोई अन्य मामला।

(25) धारा 21 के खंड (डी) के तहत, यह वित्तीय आयुक्त है, जो डिस्टिलरी के लिए लाइसेंस देने की अवधि, लाइसेंस दिए जाने की अवधि, निर्माण, भंडारण और स्प्रिट से बाहर निकलने और अन्य के संबंध

में नियम बना सकता है। आसवनी के कामकाज से संबंधित मामले। धारा 20 और 21 के संचयी पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्राधिकारी, जो डिस्टिलरी को बंद करने में सक्षम है, जिसके संबंध में लाइसेंस दिया गया है, वित्तीय आयुक्त है।

(26) धारा 21 का खंड (बी) सामान्य तौर पर वित्तीय आयुक्त को उसके द्वारा दिए गए एआई लाइसेंस के तहत स्थापित किसी भी डिस्टिलरी को बंद करने की शक्ति प्रदान करता है। यह खंड उसके द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत स्थापित किसी भी डिस्टिलरी को बंद करने को संदर्भित करता है। अभिव्यक्ति, 'किसी भी डिस्टिलरी को बंद करें' का तात्पर्य लाइसेंसधारी को डिस्टिलरी में काम करने में सक्षम बनाने वाले वित्तीय आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के निर्धारण या रद्दीकरण से है। अधिनियम की धारा 36 में विभिन्न आधार प्रदान किए गए हैं, जिनके आधार पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वह धारा इस प्रकार चलती हैः–

"राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, इस अधिनियम के तहत कोई भी लाइसेंस, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी इसे रद्द या निलंबित कर सकता है–

(ए) यदि इसे उक्त प्राधिकारी की अनुमति के बिना इसके धारक द्वारा हस्तांतरित या उप–किराए पर दिया जाता है; या

(बी) यदि उसके धारक द्वारा देय शुल्क का कोई शुल्क विधिवत भुगतान नहीं किया गया है; या

(सी) ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के धारक द्वारा या उसके नौकरों द्वारा, या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्त या निहित अनुमति के साथ ऐसे लाइसेंस के किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, परमिट या पास; या

(डी) यदि उसके धारक को राजस्व से संबंधित किसी अन्य कानून, या किसी संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध या खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 या व्यापारिक चिह्न अधिनियम के तहत दंडनीय किसी

अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। , 1889, या भारतीय दंड संहिता की धारा 482 से 489 (दोनों सम्मिलित) के तहत दंडनीय कोई अपराध; या

(ई) यदि उसके धारक को किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है, तो समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 167 के खंड (8) में देखें; या

(एफ) जहां इस अधिनियम के तहत पट्टे के अनुदान प्राप्तकर्ता के आवेदन पर लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान किया गया है, ऐसे अनुदान प्राप्तकर्ता की लिखित मांग पर; या

(छ) इच्छानुसार, यदि लाइसेंस या परमिट की शर्तों में ऐसे रद्दीकरण या निलंबन का प्रावधान है।

(27) धारा 36 के खंड (जी) के अनुसरण में लाइसेंस का निर्धारण किया गया है। उस धारा के तहत लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी को इसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है. लाइसेंस वित्तीय आयुक्त

द्वारा जारी किया गया है, वह ही उस धारा के खंड (जी) के तहत इसे निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

(28) नोटिस में उल्लिखित लाइसेंस के निर्धारण की शक्ति नियमों के नियम 7 के तहत भी प्रयोग योग्य है। वह नियम निम्नानुसार चलता हैः – "लाइसेंस उस अवधि की सीमा के बिना दिए जाते हैं, जिसके लिए वे लागू होते हैं, लेकिन शर्तों की शाखा के लिए रद्द किया जा सकता है, या एक वर्ष के नोटिस के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"

(29) इस नियम के अनुसार, बिना किसी सीमा के दिए गए लाइसेंस को उस अवधि तक निर्धारित करने का अधिकार, जिसके लिए वह क्रियाशील है, वित्तीय आयुक्त में निहित है। जैसा कि नोटिस द्वारा निर्धारित लाइसेंस की शर्तों और शर्तों से पता चलता है, यह 5 नवंबर, 1941 को एक अनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया गया था। इस प्रकार, इस नियम के तहत भी, यह वित्तीय आयुक्त है, जो लाइसेंस निर्धारित करने के लिए सक्षम है। . लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के तहत लाइसेंस

निर्धारित करने की शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। वह स्थिति इस प्रकार चलती है:–

शर्त संख्या 9.

"वित्तीय आयुक्त लाइसेंसधारी को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि उसका लाइसेंस नोटिस की तारीख से कम से कम एक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाएगा।"

(30) इस शर्त को अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के अनुसरण में लाइसेंस में शामिल किया गया है। वह शर्त फिर से वित्तीय आयुक्त को लाइसेंस निर्धारित करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 20, 21 और 36 के प्रावधानों को नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ जोड़ा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वित्तीय आयुक्त है, जो याचिकाकर्ता को जारी किए गए लाइसेंस का निर्धारण करने के लिए सशक्त है। .

(31) दूसरा प्रश्न जो बिंदु संख्या 1 के तहत उठता है वह यह है कि क्या श्री एस. सी. छाबड़ा, जिन्होंने याचिकाकर्ता–कंपनी को 14 दिसंबर, 1964 को नोटिस दिया था और उस समय उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, इसके हकदार थे। नोटिस जारी करें. उस नोटिस में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री छाबड़ा ने इसे पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 3779-ईटी (VI) - 64/3583 दिनांक 23 मई, 1964 के आधार पर उस क्षमता में शक्ति का प्रयोग करने के हकदार होने के नाते वित्तीय आयुक्त के रूप में जारी किया था। इस प्रकार, श्री छाबड़ा के पास वित्तीय आयुक्त के रूप में कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति थी। यह सारहीन और अप्रासंगिक है कि वह अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त भी थे। इसे चुनौती नहीं दी गई है कि उस अधिसूचना के आधार पर, श्री छाबड़ा वित्तीय आयुक्त के कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। इस प्रकार, यह तर्क कि श्री छलबरा ने उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के रूप में कार्य किया, न कि वित्तीय आयुक्त के रूप में, जिस क्षमता में वह लाइसेंस निर्धारित करने में सक्षम थे, उसमें कोई दम नहीं है।

(32) उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी को दिए गए नोटिस से पहले एक नोटिस दिया गया होगा जिसमें कंपनी को लाइसेंस के निर्धारण के खिलाफ कारण बताने के लिए कहा गया होगा और ऐसा होना चाहिए था। बोलने का आदेश पारित किया गया। यह तय करने के लिए कि क्या ऐसा कारण बताओ नोटिस आवश्यक था, हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या वित्तीय आयुक्त ने नोटिस जारी करते समय अर्ध–न्यायिक या प्रशासनिक क्षमता में कार्य किया था। यदि उन्होंने प्रशासनिक क्षमता में कार्य किया, तो क्या नोटिस जारी करने में उनके द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार की है कि याचिकाकर्ता–कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करना और कंपनी की सुनवाई करना आवश्यक था। इन सवालों का जवाब उसके द्वारा प्रयोग किए गए लाइसेंस के निर्धारण की शक्ति की प्रकृति और दायरे पर निर्भर करेगा। जैसा कि आक्षेपित नोटिस में ही दिया गया है, उन्होंने नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत लाइसेंस के

निर्धारण के लिए शक्ति का प्रयोग किया। धारा 21(बी) जैसा कि पहले बिंदु की चर्चा के दौरान पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह प्रावधान करता है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत स्पिरिट निर्माण के लिए स्थापित डिस्टिलरी को बंद किया जा सकता है। विभिन्न आधार, जिन पर किसी डिस्टिलरी को बंद किया जा सकता है या दूसरे शब्दों में उसका लाइसेंस निलंबित, रद्द या निर्धारित किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों में दिए गए हैं जैसा कि पहले दोहराया गया है। प्रासंगिक खंड उस धारा का खंड (जी) है। जैसा कि उस खंड में दिया गया है, एक लाइसेंस को इच्छानुसार रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेंस की शर्तों में ऐसे रद्दीकरण का प्रावधान है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि लाइसेंस में शामिल किसी शर्त के द्वारा, लाइसेंसिंग प्राधिकारी और लाइसेंसधारी परस्पर सहमत होते हैं कि लाइसेंस उस प्राधिकारी द्वारा बताए बिना किसी कारण के रद्द किया जा सकता है, तो लाइसेंस ऐसे रद्दीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। पहले उल्लिखित लाइसेंस की शर्त संख्या 9, लाइसेंसिंग प्राधिकारी और लाइसेंसधारी द्वारा तैयार और पारस्परिक रूप से सहमत है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित

रूप में नोटिस दे सकता है कि लाइसेंस एक वर्ष से कम की समाप्ति पर निर्धारित नहीं किया जाएगा। नोटिस की तारीख से. लाइसेंस की इस शर्त से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जैसा कि याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लाइसेंस बिना किसी कारण बताए धारा 36 के खंड (जी) द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए उत्तरदायी है, जिसके अनुसरण में यह शर्त डाली गई थी और कंपनी द्वारा एक संविदात्मक दायित्व स्वीकार किया गया। लाइसेंस के निर्धारण की शर्त के साथ जोड़ी गई एकमात्र सीमा यह है कि लाइसेंस के निर्धारण के लिए जारी नोटिस की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। माना कि दिया गया नोटिस निर्धारित अवधि के लिए है। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 अनुबंध की शर्त है। याचिकाकर्ता कंपनी का मामला यह नहीं है कि वह अनुचित प्रभाव या दबाव के तहत या लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से किसी धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी पर सहमत हुई थी। यह स्वेच्छा से स्वीकृत शब्द है। कंपनी ने लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसके तहत की जाने वाली किसी भी समय कार्रवाई के लिए लाइसेंस की समाप्ति के परिणाम के बारे में खुली आँखों से उस शर्त को स्वीकार कर लिया है। अनुबंध की

यह शर्त पिछले तीस वर्षों से लाइसेंस में विद्यमान है। अनुबंध की एक पार्टी के रूप में, याचिकाकर्ता–कंपनी इससे बंधी है।

(33) याचिकाकर्ता–कंपनी अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) में निर्धारित इस शर्त को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थी। ऐसी किसी शर्त पर सहमत होना या न होना पूरी तरह से उसके विवेक और उसकी प्यारी पसंद पर निर्भर था। इसे स्वीकार करने और इसका पालन करने के लिए सहमत होने के बाद, याचिकाकर्ता–कंपनी यह नहीं कह सकती कि वह इससे बाध्य नहीं है। यह शर्त अनुबंध की शर्त होने के कारण, याचिकाकर्ता कंपनी इसके खिलाफ दलीलें देकर बच नहीं सकती है। यह लाइसेंस के अनुबंध की इस पारस्परिक रूप से सहमत शर्त के तहत है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने लाइसेंस को उसमें दिए गए अनुसार निर्धारित करने के लिए नोटिस दिया है। लाइसेंस के अनुबंध की शर्त संख्या 9 के तहत याचिकाकर्ता–कंपनी को नोटिस जारी करना, जिसके तहत उसे समाप्त किया जा सकता है, पूरी तरह से एक प्रशासनिक अधिनियम है और ऐसा करने वाला प्राधिकारी प्रशासनिक

क्षमता में कार्य करता है, न कि अर्ध–न्यायिक क्षमता में। इस प्रकार, यह नोटिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक क्षमता में जारी किया गया था, न कि अर्ध–न्यायिक क्षमता में।

सक्रिय क्षमता में और अर्ध–न्यायिक क्षमता में नहीं।

(34) याचिकाकर्ता–कंपनी लाइसेंस की शर्त संख्या 9 में एक पक्ष होने के नाते इस तथ्य से अवगत थी कि लाइसेंस बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। शब्द की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्टीकरण के माध्यम से कोई बचाव नहीं दे सकता क्योंकि यह इससे बंधा हुआ है। न तो अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) में, न ही उसके तहत बनाए गए नियमों में, न ही शर्त संख्या 9 में या यहां तक कि लाइसेंस की किसी भी अन्य शर्त में, नोटिस जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 पर कोई व्यक्त या निहित दायित्व है। या शर्त संख्या 9 के तहत नोटिस जारी होने से पहले याचिकाकर्ता–कंपनी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करना। याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से इस बिंदु पर बहस

करते हुए पूछा गया कि क्या वह ऐसे किसी प्रावधान या शर्त की ओर इशारा कर सकते हैं जिससे यह संकेत मिलता हो कि शर्त संख्या 9 के तहत नोटिस जारी होने से पहले कंपनी को सुना जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सकते। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों की आवश्यकता है कि विवादित नोटिस जारी करने से पहले, याचिकाकर्ता–कंपनी को सुना जाना चाहिए और उस अवसर को वहन करने के लिए, कारण बताओ नोटिस विवादित नोटिस जारी करने से पहले होना चाहिए। . प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू करने का प्रश्न उन मामलों में उठता है जहां किसी विवादग्रस्त मामले पर वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित एक पक्ष के खिलाफ निर्णय लिया जाना होता है और वैधानिक प्रावधान ऐसे पक्ष की सुनवाई से पहले होने के लिए मौन होते हैं। विवाद तय हो गया है. पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद का निर्धारण करने और कुछ सबूतों पर विचार करने की आवश्यकता वाले वैधानिक दायित्व वाले

क़ानून के तहत कार्य करने वाला एक प्राधिकारी अर्ध–न्यायिक क्षमता में कार्य करेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना और उन्हें सुने बिना कोई निर्णय दिया जाता है, तो प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा, भले ही सुनवाई का अवसर प्रदान करने और ऐसी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान न हो। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 की प्रकृति और किसी वैधानिक या अन्यथा सुनवाई की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी ने पूरी तरह से प्रशासनिक क्षमता में कार्य किया है। लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए उसे किसी सबूत पर विचार नहीं करना होगा। इसे केवल शर्त संख्या 9 को देखना था और लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस देना था। याचिकाकर्ता का अधिकार – कंपनी को सुना जाना और उसके बचाव पर विचार किया जाना उस शर्त की सामग्री से अलग है। शर्त संख्या 9 के दायरे के अनुसार, शर्त संख्या 9i के तहत नोटिस जारी करना या न जारी करना पूरी तरह से वित्तीय आयुक्त के विवेक में है, जबकि उस शर्त के तहत कार्रवाई करते समय किसी भी विवाद पर कोई निर्णय नहीं देना था। इसके तहत

विवादित नोटिस देना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किए बिना प्रशासनिक क्षमता में कार्रवाई करना है। पट्टे या लाइसेंस के एक समझौते में, उदाहरण के लिए अचल संपत्ति के संबंध में, पट्टेदार या लाइसेंसकर्ता के रूप में राज्य और पट्टेदार या लाइसेंसधारी के रूप में दूसरे पक्ष के बीच किया गया अनुबंध, जिसमें निर्धारित के लिए नोटिस जारी करके पट्टे या लाइसेंस की समाप्ति की अवधि शामिल है। समय की अवधि में, ऐसे पट्टेदार या लाइसेंसधारी के लिए वैध रूप से यह दावा करना खुला नहीं है कि पट्टे या लाइसेंस को समाप्त करने के लिए ऐसा नोटिस जारी करने से पहले, दूसरे पक्ष को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के तहत कार्रवाई करते समय वित्तीय आयुक्त की शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता–कंपनी की सुनवाई की मांग पर विचार करने की उपेक्षा की गई है। प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति। याचिकाकर्ता कंपनी को उसके जारी होने से पहले नोटिस जारी करने की बाध्यता के बिना प्रशासनिक क्षमता में लाइसेंस समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग किया

गया है, कारण बताओ नोटिस के अभाव में नोटिस की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

(35) लाइसेंस में मौजूद शर्त संख्या 9 के साथ, याचिकाकर्ता–कंपनी का लाइसेंसधारी के रूप में बने रहने का अधिकार, यदि इसे किसी भी अधिकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एक अक्षम्य अधिकार है। इसे किसी भी समय हराया जा सकता है. इस शर्त के साथ लाइसेंस बरकरार रहने पर लाइसेंस केवल डिस्टिलरी में काम करने की अनुमति बन जाता है, बशर्ते लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसकी समाप्ति के लिए एक वर्ष का नोटिस दे। शर्त संख्या 9 ने लाइसेंस को डिस्टिलरी में काम करने के लिए दिया गया विशेषाधिकार बना दिया है। उस शर्त के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने उसमें दिए गए नोटिस के अनुसार किसी भी समय लाइसेंस वापस लेने का अधिकार और शक्ति अपने पास बरकरार रखी है। याचिकाकर्ता कंपनी इसे वापस लेने या रद्द करने का विरोध नहीं कर सकती। शर्त संख्या 9 के तहत नोटिस जारी करने के लिए कार्य करने के उद्देश्य से, वित्तीय आयुक्त को अलग या औपचारिक आदेश दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे केवल उस शर्त

के संदर्भ में नोटिस जारी करना है। अर्ध–न्यायिक क्षमता में कार्य न करने और यहां तक कि प्रशासनिक क्षमता में कार्य करते समय भी, वित्तीय आयुक्त के लिए संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है, शर्त संख्या 9 के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। एक औपचारिक आदेश, तर्कपूर्ण या मौखिक आदेश से तो बिलकुल भी नहीं। यदि अधिनियम की धारा 36 के खंड (ए) से (एफ) के तहत उन खंडों में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट या उल्लंघन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या इनमें से किसी एक का अनुपालन करने में विफलता होती है लाइसेंस की शर्तें लाइसेंस की शर्त संख्या 7 में दी गई हैं, कारण बताओ नोटिस आवश्यक है। वर्तमान मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए जारी किया गया नोटिस धारा 36 के खंड (जी) द्वारा शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ा जाता है, न कि किसी खंड (ए) से (एफ) या लाइसेंस की किसी अन्य शर्त द्वारा। .

(36) इस तर्क के समर्थन में कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, प्रतिवादी संख्या 2 ने लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस जारी करते समय अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया और उस नोटिस को जारी करने से पहले याचिकाकर्ता–कंपनी को उचित अवसर देना चाहिए था। , सुखलाल सेन बनाम कलेक्टर, जिला सतना और अन्य (1) पर भरोसा रखा गया था। उस मामले में, लाइसेंस रद्द करने का नोटिस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मध्य प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की संख्या II की धारा 31 (एल) (बी) के तहत जारी किया गया था। उस अधिनियम की धारा 31 पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की संख्या XIV की धारा 36 के खंड (सी) के समान क्षेत्र में है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी भी खंड (ए) से (£) का अनुपालन करने में विफलता अधिनियम की धारा 36 के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी की ओर से चूक हो जाती है और चूक के लिए लाइसेंसधारी से शुल्क लिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप नोटिस जारी करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, साथ ही लाइसेंसधारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलता है। वह डिफ़ॉल्ट.

यह अधिनियम की धारा 36 के खंड (ए) से (एफ) के तहत एक लाइसेंसधारी द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट के आधार पर है कि प्रतिवादी नंबर 2 अर्ध–न्यायिक क्षमता में कार्य करता है और परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस आयोजित किया गया है। आवश्यक होना। वर्तमान मामले का धारा 36 के किसी भी खंड से कोई लेना–देना नहीं है। नोटिस धारा 36 के खंड (जी) के अनुसरण में शर्त संख्या 9 के तहत जारी किया गया था, जो लाइसेंसधारी की ओर से किसी भी डिफ़ॉल्ट से संबंधित नहीं है लेकिन उस शर्त के दायरे में लाइसेंस रद्द करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के प्रकाश से संबंधित है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण मानने वाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले के अनुरूप नहीं है और स्पष्ट रूप से अलग है।

(37) इस दलील के समर्थन में अगला मामला कि याचिकाकर्ता कंपनी हमारे सामने उद्धृत लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस की

सेवा से पहले नोटिस जारी करने की हकदार है, डी.एफ.ओ. दक्षिण खीरी एवं अन्य बनाम राम सनेही सिंह (2)। यह मामला जिला वन अधिकारी द्वारा आयोजित नीलामी से संबंधित है। निश्चित अवधि के लिए जंगल की लकड़ी काटने के अधिकार की नीलामी में प्रतिवादी राम सनेही सिंह की बोली स्वीकार कर ली गई। प्रतिवादी ने उस अवधि से अधिक समय तक लकड़ी काटी। जिला वन अधिकारी ने प्रतिवादी को अनुबंध की अवधि के बाद काटी गई लकड़ी को हटाने की अनुमति दी। प्रभागीय वन अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की अवधि के बाद काटी गई लकड़ी को उसके द्वारा विनियोजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि अनुबंध की अगली अवधि के लिए विनियोजित किया जा सकता है। प्रतिवादी ने प्रभागीय वन अधिकारी को अपने आदेश को प्रभावी करने से रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए निषेधाज्ञा रिट की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपील पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रतिवादी की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। इन तथ्यों

पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया कि प्रतिवादी को लकड़ी काटने और हटाने के मामले में उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित करने की मांग की गई थी और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में आदेश देने के बाद, प्रभागीय वन अधिकारी को आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ अधिकारी के आदेश को रद्द करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रतिवादी से स्पष्टीकरण मांगे बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। उस मामले में, प्रतिवादी को कटी हुई लकड़ी की संपत्ति से वंचित करने की मांग की गई थी, जिसे उसने हटा दिया था और उसकी बात सुने बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया गया था। यह माना गया कि भले ही प्रभागीय वन अधिकारी अर्ध-न्यायिक क्षमता के बजाय प्रशासनिक रूप से कार्य कर रहा था, लकड़ी की बहाली का आदेश प्रतिवादी के पूर्वाग्रह के तहत उसे पहले के रद्दीकरण के खिलाफ स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। आदेश देना। वर्तमान मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित पहले के आदेश को रद्द करने का सवाल ही शामिल नहीं है। यह अनुबंध की शर्त की शर्तों पर

है कि याचिकाकर्ता कंपनी से किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना एक नोटिस, जो पूरी तरह से प्रशासनिक नोटिस है, उस शर्त के अनुसार स्वीकार्य रूप से जारी किया गया था। शर्त संख्या 9 के तहत नोटिस की तामील से याचिकाकर्ता–कंपनी के संपत्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। याचिकाकर्ता–कंपनी को डिस्टिलरी चलाने में सक्षम बनाने के लिए जारी किया गया लाइसेंस लाइसेंस के कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि उसने सहमति व्यक्त की है। याचिकाकर्ता–कंपनी शर्त संख्या 9 सहित विभिन्न शर्तों से बंधी है। डिस्टिलरी चलाने का अधिकार उस शर्त के अधीन है। डिस्टिलरी के परिसर में जो भी संपत्ति है और परिसर स्वयं याचिकाकर्ता–कंपनी का है। आक्षेपित नोटिस जारी करके, प्रतिवादी संख्या 2 ने किसी भी तरह से अधिनियम के किसी भी प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों या लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। उन प्रावधानों के अधीन, संपत्ति अभी भी याचिकाकर्ता कंपनी में निहित है जैसा कि अन्यथा होता था।

(38) कारण बताओ नोटिस जारी करने के दावे के लिए याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से जिस अगले निर्णय पर भरोसा किया गया वह मेसर्स महाबीर प्रसाद संतोष कुमार बनाम यूपी राज्य है। और अन्य (3). इस मामले में, अपीलकर्ताओं के पास दो लाइसेंस थे, एक यू.पी. के तहत। चीनी व्यापारियों का लाइसेंसिंग आदेश, 1962 यू.पी. के तहत चीनी और अन्य में व्यापार करने के लिए। खाद्यान्नों के व्यापार के लिए खाद्यान्न डीलरों का लाइसेंसिंग आदेश, 1964। 5 जून, 1967 को अपीलकर्ताओं को उनकी दुकान के निरीक्षण में पाई गई कुछ अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। अगले दिन, उन्हें अपने चीनी और आटे के स्टॉक को बिंदकी सहकारी विपणन समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया और उन्हें चीनी और आटे के स्टॉक को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। 28 जून, 1967 को पत्र द्वारा अपीलकर्ताओं को सूचित किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उन्होंने उस आदेश की वैधता को चुनौती दी। यू.पी. की धारा 7 के तहत स्टॉक को रद्द करने और सरेंडर करने का आदेश पारित किया गया था। चीनी डीलरों का

लाइसेंसिंग आदेश और यू.पी. की धारा 11 के तहत। खाद्यान्न विक्रेताओं का लाइसेंसिंग आदेश। इन दोनों आदेशों के क्रमशः खंड 8 और 12 में स्टॉक को रद्द करने और सरेंडर करने के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है। न केवल रद्द करने के आदेशों में कोई कारण नहीं बताया गया, बल्कि अपीलें भी बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी गईं। जैसा कि इन खंडों के प्रावधानों से पता चलता है, ये आदेश तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक अपीलकर्ताओं पर उन आदेशों को पारित करने के लिए अनियमितताओं का आरोप नहीं लगाया गया और इसलिए उन आरोपों के जवाब में सुना गया और उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया। अपील के प्रावधानों से पता चलता है कि आदेश अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा रहे थे। यह मामला भी अलग है और किसी भी तरह से मौजूदा मामले के समानांतर नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें लाइसेंस रद्द करने और अपीलकर्ताओं को उनके स्टॉक से वंचित करने की शक्ति से संबंधित वैधानिक प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट पर अपीलकर्ताओं को सुनने के लिए बाध्य करते हैं, इससे पहले कि उन्हें कुछ अनियमितताओं के

लिए दोषी ठहराया जा सके। उन्हें। इन नियंत्रण आदेशों की शर्तों की प्रकृति और दायरे धारा 36 के खंड (ए) से (एफ) के अनुरूप हैं, न कि लाइसेंस की शर्त संख्या 9 में प्रदान किए गए अनुबंध की अवधि के प्रकार से कोई लेना–देना है। उस धारा के खंड (जी) का अनुसरण।

(39) उत्तरदाताओं की ओर से प्रेम नाथ भल्ला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (4) में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था, इस प्रस्ताव के लिए कि याचिकाकर्ता–कंपनी को दिया गया नोटिस प्रशासनिक प्रकृति का है और नहीं कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। रिट–याचिकाकर्ता प्रेम नाथ भल्ला को पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, संख्या 11, 1931 की धारा 3 के तहत पांच साल के लिए इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि उन्हें सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। जब उन्हें हटाया गया, तो उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था और परिणामस्वरूप इसके अभाव में उन्हें हटाने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था। यह नियुक्ति उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा

(7) के तहत की गई थी। उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) के आधार पर, उन्हें सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह माना गया कि जब कोई कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति स्वीकार करता है, भले ही नगरपालिका समिति उसे एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त कर रही हो, फिर भी सरकार को उसकी नियुक्ति के 15 दिनों के बाद भी किसी भी समय उसे हटाने का अधिकार है, इन परिस्थितियों में, वह नहीं कर सकता शिकायत करें कि उसे पूरी अवधि के लिए पद पर रहने का अधिकार है, कि वह जानता है कि उसकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं, कि यदि राज्य द्वारा उप–धारा (7) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है। सरकार ने उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि उन्हें क्यों और किस आधार पर और किस कारण से हटाया जा रहा है और वह अपने पद से हटाए जाने से पहले किसी भी कारण बताओ नोटिस का दावा नहीं कर सकते हैं और न ही उनके पास कोई कारण है। अपनी नियुक्ति के समय निर्धारित पूरी अवधि तक पद पर बने रहने का अधिकार। आगे यह देखा

गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तभी लागू होते हैं जब किसी को किसी पद का अधिकार मिल जाता है और भले ही उसकी नियुक्ति की शर्तें यह नहीं कहती हैं कि 'उसकी सेवाएं समाप्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।' फिर भी उन्हें अपने कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहने से पहले ऐसा नोटिस दिया जाना चाहिए। पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) का दायरा अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के साथ पढ़ी जाने वाली शर्त संख्या 9 के समान है। दोनों में बिना कोई कारण बताए नोटिस देने और निश्चित अवधि के लिए नोटिस दिए जाने के बाद नौकरी समाप्त करने का प्रावधान है। वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा दायरे और प्रकृति में उपरोक्त उद्धृत मामले में उत्पन्न बिंदु के समान है। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 की प्रकृति लाइसेंसधारी को दिए जाने वाले लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के किसी भी दायित्व के विचार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है।

(40) प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुपालन का प्रश्न तभी उठता है जब वैधानिक प्रावधानों में यह संकेत हो कि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की जाती है। प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं होते हैं और उनकी प्रयोज्यता तब तक आकर्षित नहीं की जा सकती जब तक कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान उन्हें लागू करने की आवश्यकता की दिशा में इंगित न करें। शर्त संख्या 9, जो अनुबंध की एक शर्त है, लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस की सेवा से संबंधित है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी पर ऐसे किसी दायित्व के होने का दूर–दूर तक कोई विचार नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी, जिसका कार्यकाल 55 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया गया था, के दावे की निरंतरता पर विचार करते समय, जब उसने सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर ली, तो भारत संघ बनाम जे.एन. सिन्हा और अन्य (5) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने खारिज कर दिया। वह निम्नलिखित शर्तों में दावा करता हैः –

“मौलिक नियम 56 (जे) (सिविल सेवा मौलिक नियम) के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर दिया जाए। भारत संघ के अधीन सेवारत एक सरकारी कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 310 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करता है। लेकिन यह 'खुशी' सिद्धांत अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों या कानून के साथ–साथ अनुच्छेद 311 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन है। प्राकृतिक न्याय के नियम सन्निहित नियम नहीं हैं और न ही उन्हें मौलिक अधिकारों की स्थिति तक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि क्रेपक बनाम भारत संघ (6) में इस न्यायालय ने देखा, 'प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या न्याय के गर्भपात को रोकना है। ये नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे कानून का स्थान नहीं लेते बल्कि उसे पूरक बनाते हैं।' यह सच है कि यदि किसी वैधानिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालयों को ऐसा करना

चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधायिका और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। लेकिन, दूसरी ओर, यदि कोई वैधानिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के किसी या सभी नियमों या सिद्धांतों के आवेदन को बाहर करता है, तो न्यायालय विधायिका या वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसमें पढ़ सकता है। संबंधित प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं, यह शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान के स्पष्ट शब्दों, प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है और पर निर्भर करता है। उस शक्ति के प्रयोग का प्रभाव.................

443

करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल बनाम पंजाब राज्य, आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति .)

अब मूल नियम 56(जे) के स्पष्ट शब्दों पर आते हैं, तो यह कहता है कि उपयुक्त प्राधिकारी को एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है यदि उसकी राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। उपयुक्त प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार पूर्ण है। उस शक्ति का प्रयोग नियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जिनमें से एक यह है कि संबंधित प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। यदि वह प्राधिकारी प्रामाणिक रूप से वह राय बनाता है, तो उस राय की सत्यता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। पीड़ित पक्ष यह दावा करने के लिए स्वतंत्र है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या निर्णय संपार्श्विक आधार पर आधारित है या यह एक मनमाना निर्णय है।

(41) याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा बिंदु संख्या 3 के तहत यह तर्क उठाया गया है कि कंपनी का लाइसेंस रद्द करने से संपत्ति रखने और उसका निपटान करने का अधिकार और अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार प्रभावित होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के

उप–खंड (एफ) और (जी) में क्रमशः शराब के निर्माण और बिक्री को शामिल किया गया है, याचिकाकर्ता कंपनी के पास रिट याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के खंड (ए) से (जी) में निहित मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल नागरिकों को दी गई है। नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्ति उन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता–कंपनी एक लिमिटेड कंपनी और निगमित निकाय होने के नाते और नागरिक नहीं होने के कारण अपने उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने वाली रिट याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। ऐसी याचिका को बनाए रखने का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, न कि याचिकाकर्ता–कंपनी जैसे निकायों को शामिल करने के लिए। इस बिंदु पर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य (7) मामले में सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया था। उनका आधिपत्य इस प्रकार मनाया गयाः –

“नागरिकता और राष्ट्रीयता के बीच अंतर के संबंध में हमने जो पहले ही कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि निगमों की राष्ट्रीयता उनके निगमन के देश के अनुसार हो सकती है; लेकिन यह जरूरी नहीं कि उन्हें नागरिकता प्रदान करे। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि संविधान का भाग ॥ जब नागरिकता से संबंधित है तो केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को संदर्भित करता है। इसे नागरिकता अधिनियम द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है जो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित है और इसे केवल प्राकृतिक व्यक्तियों तक ही सीमित रखता है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस देश के ऐसे नागरिक भी हो सकते हैं, जो न तो संविधान के भाग ॥ के चार कोनों के भीतर पाए जाते हैं और न ही नागरिकता अधिनियम के चार कोनों के भीतर पाए जाते हैं। हमारी राय है कि ये दो प्रावधान इस देश के नागरिकों के लिए संपूर्ण होने चाहिए, भाग ॥ संविधान लागू होने की तारीख पर नागरिकों से संबंधित है और नागरिकता अधिनियम उसके बाद नागरिकों से संबंधित है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि ये दोनों प्रावधान इस देश के नागरिकों के लिए पूरी तरह से संपूर्ण हैं और

ये नागरिक केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही हो सकते हैं। यह तथ्य कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोजनों के लिए निगम देश के नागरिक हो सकते हैं, उन्हें नगरपालिका कानून या संविधान के प्रयोजनों के लिए इस देश का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। न ही हम यह सोचते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त 'नागरिक' शब्द का प्रयोग संविधान के भाग II में जिस अर्थ में किया गया था, उससे भिन्न अर्थ में किया गया था।"

(42) सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आधिकारिक आदेश के सामने, याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह खंड (1) के उप–खंड (एफ) या उप–खंड (जी) के उल्लंघन के आधार पर अपना दावा कर सके।) संविधान के अनुच्छेद 19 का.

(43) योग्यता के आधार पर भी, इन दो उप–खंडों के तहत याचिकाकर्ता–कंपनी के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उठाए गए बिंदु में कोई बल नहीं है। याचिकाकर्ता–कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की सूचना की सेवा द्वारा, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने लाइसेंस की शर्त

संख्या 9 के संदर्भ में, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, लाइसेंसधारी और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के बीच अनुबंध की एक शर्त है, अधिकार बंद कर दिया है याचिकाकर्ता की– शराब बनाने वाली कंपनी। याचिकाकर्ता–कंपनी को दिए गए नोटिस के अनुसरण में लाइसेंस रद्द होने के बावजूद प्रतिवादी किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता–कंपनी ने सुपरस्ट्रक्चर सहित डिस्टिलरी के परिसर को अपना बनाए रखा है और वह अपनी इच्छानुसार इसका निपटान करने की हकदार है। लाइसेंस की शर्त संख्या 1 के आधार पर, याचिकाकर्ता कंपनी ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए सभी नियमों का पालन करने का वचन दिया। शर्त संख्या 5 के आधार पर, याचिकाकर्ता–कंपनी बनाए रखे जाने वाले स्पिरिट या सामग्री के स्टॉक और अन्य सभी मामलों के संबंध में वित्तीय आयुक्त के सभी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हुई, जिसमें अनुपालन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है। लाइसेंस की शर्त संख्या 11 इस प्रकार प्रदान करती हैः –

“पिछली शर्तों के तहत लाइसेंस के निरसन, रद्दीकरण या निर्धारण के तहत, लाइसेंसधारी या उसका प्रतिनिधि तुरंत डिस्टिलिंग बंद कर देगा और इमारतों और संयंत्र का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करना बंद कर देगा जिसके लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया था। न तो लाइसेंसधारी और न ही कोई व्यक्ति लाइसेंस के निरस्तीकरण, रद्दीकरण या निर्धारण के संबंध में किसी भी मुआवजे या क्षति का हकदार होगा।

(44) लाइसेंस की समाप्ति के बाद, डिस्टिलरी की इमारत और संयंत्र याचिकाकर्ता कंपनी की संपत्ति बने रहे। जो नियम संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप–खंड (एफ) से संबंधित तर्क के बिंदु पर प्रासंगिक है, वह नियमों का नियम 10 है। वह नियम इस प्रकार चलता हैः–

"यदि कोई लाइसेंस रद्द किया जाता है, रद्द किया जाता है या निर्धारित किया जाता है, तो लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के तहत, अपने स्पिरिट, उपकरण, भंडारण जहाजों और अन्य आसवन

संयंत्र के स्टॉक का निपटान ऐसे तरीके से करेगा जैसा वित्तीय आयुक्त निर्देशित कर सकता है।"

याचिकाकर्ता–कंपनी ने नियम 10 का पालन करने का वचन दिया है, उसके लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि उस नियम के संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 2 के पास स्पिरिट, उपकरण, भंडारण, जहाजों और अन्य आसवन के अपने स्टॉक का निपटान करने की कोई शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ता–कंपनी का प्लांट इस तरह से लगाया जाए जैसा प्रतिवादी नंबर 2 आवश्यक समझे। किसी भी स्थिति में, ऐसा कोई आदेश पारित करने की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को एक कंपनी होने और नागरिक न होने के नाते वर्तमान याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता–कंपनी ऐसे उपाय की तलाश कर सकती है जो नियमों के नियम 10 के अंतर्गत आने वाले निपटान के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश पारित होने के परिणामस्वरूप उसके लिए खुला हो। याचिकाकर्ता–कंपनी ने नियम 10 का पालन करने का वचन दिया है, वह उस तरीके से बंधी है जिसमें

प्रतिवादी नंबर 2 नियम 10 के अंतर्गत आने वाली सभी चीजों का निपटान करता है।

(45) इसी तरह, याचिकाकर्ता–कंपनी वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकती है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी उसके लाइसेंस के निर्धारण के नोटिस के आधार पर, व्यवसाय करने की उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता–कंपनी शराब का निर्माण या बिक्री करने की कोई स्वतंत्रता या अधिकार होने का दावा नहीं कर सकती। इसका लाइसेंस इसकी शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों से घिरा हुआ है, जिसके अनुपालन के लिए याचिकाकर्ता–कंपनी उन शर्तों और प्रावधानों से बंधी है। शराब बनाने का उसका अधिकार, अगर इसे बिल्कुल भी अधिकार कहा जा सकता है, लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के तहत समाप्त किया जा सकता है। इसी शर्त के तहत याचिकाकर्ता–कंपनी को विवादित नोटिस भेजा गया है। यह शराब निर्माण का कार्य तब तक कर सकता है जब तक कि लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के तहत उससे यह अधिकार नहीं छीन लिया जाता है।

यह एक शर्त या प्रतिबंध है जिसे याचिकाकर्ता स्वेच्छा से उस पर लगाने के लिए सहमत हुआ है और उसे इसका सम्मान करना चाहिए। शराब बनाना याचिकाकर्ता–कंपनी का पूर्ण अधिकार नहीं है। यह उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिनके अधीन याचिकाकर्ता–कंपनी ने खुद को रखा है, जिसमें सहमति के अनुसार एक नोटिस पर लाइसेंस की शर्त निर्धारित करना, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उस पर तामील किया जाना शामिल है। शर्त संख्या 9 और लाइसेंस की अन्य प्रासंगिक शर्तों और नियमों के नियम 7 के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध शराब जैसी वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उचित प्रतिबंध हैं और आम जनता के हित में हैं। याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह उनका पालन करने के लिए सहमत होने के बाद उन पर आपत्ति जताए।

(46) अजमेर एक्साइज रेगुलेशन, 1915 में दिए गए अनुसार एक्साइज के प्रशासन से संबंधित विधायी विनियमन द्वारा प्रतिबंध लगाने की वैधता के बारे में प्रश्न कूवर्जी बी. भरूचा, याचिकाकर्ता बनाम सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उत्पाद शुल्क

आयुक्त एवं अन्य, उत्तरदाता (8)। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक सार्वजनिक नीलामी में, एक विक्रेता की दुकान को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टे पर दे दिया गया था। वह बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस–शुल्क जमा करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया कि उसके मामले पर विचार किया जाए ताकि उसे विक्रेता की दुकान के लिए लाइसेंस दिया जा सके। हालाँकि, प्रतिवादी उत्पाद शुल्क आयुक्त ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और बोली लगाने वाले की ओर से समय के भीतर राशि जमा करने में विफलता के बावजूद बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 (एल) (जी) के प्रावधानों के आधार पर उसे शराब की बिक्री का कारोबार करने का मौलिक अधिकार है और अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अनुमति न देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। याचिकाकर्ता को दिया गया लाइसेंस अनुच्छेद 19(एल)(जीएल) के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

उस विवाद को निरस्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने इस प्रकार टिप्पणी कीः –

“संविधान का अनुच्छेद 19(1) (जी) गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है और अनुच्छेद का खंड (6) कानून को अधिकृत करता है जो इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। आम जनता के हित में. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिबंध की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए व्यवसाय की प्रकृति और उस व्यापार में प्रचलित स्थितियों का ध्यान रखना होगा। यह स्पष्ट है कि ये कारक व्यापार से व्यापार में भिन्न होने चाहिए और सभी व्यापारों के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के पास उन व्यापारों पर रोक लगाने की शक्ति है, जो अवैध या अनैतिक हैं या जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हैं।”

"हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार या महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने वाले कानूनों को निषेध लागू करने के रूप में अवैध नहीं माना जा सकता है, न कि केवल एक विनियमन के रूप में। इसलिए, प्रतिबंधों की तर्कसंगतता तय करने में व्यवसाय की प्रकृति एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी वैध व्यापार या व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार स्पष्ट रूप से ऐसे उचित विचारों के अधीन है, जिसे देश के शासी प्राधिकारी द्वारा समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शांति, व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक माना जा सकता है। कुछ व्यवसायों में उनके द्वारा किए जाने वाले शोर के कारण, कुछ में उत्पन्न होने वाली गंध के कारण और कुछ में उनके साथ आने वाले खतरों के कारण उस इलाके के संबंध में विनियमों की आवश्यकता होती है जिसमें वे आयोजित किए जा सकते हैं। कुछ, उपयोग की गई, निर्मित या बेची गई वस्तुओं की खतरनाक प्रकृति के कारण, उन्हें उपयोग करने, निर्माण करने या बेचने की अनुमति देने वाली पार्टियों में विशेष योग्यता की भी आवश्यकता होती है।

(47) शराब जैसे नशीले पदार्थों के संबंध में व्यापार करने की स्वतंत्रता के संबंध में विधायी प्रतिबंधों की शक्ति पर विचार करते समय, उनके आधिपत्य ने सी रो लेई बनाम क्रिस्टेंसन (9) से निम्नलिखित अंशों को अनुमोदन के साथ पुनः प्रस्तुत कियाः –

"इसलिए, इस तरह से शराब की बिक्री, हर समय, हर राज्य की अदालतों द्वारा विधायी विनियमन का उचित विषय मानी जाती रही है। शराब के एक गिलास को इस प्रकार निपटाने से पहले न केवल सैलून के संचालक से लाइसेंस लिया जा सकता है, बल्कि उन व्यक्तियों के वर्ग के बारे में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिन्हें वे बेची जा सकती हैं और दिन के घंटे और समय पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सप्ताह के वे दिन, जिन दिन सैलून खोले जा सकते हैं। उनकी बिक्री उस रूप में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यह सार्वजनिक सुविधा और सार्वजनिक नैतिकता का सवाल है न कि संघीय कानून का।"

"राज्य की पुलिस शक्ति व्यवसाय को विनियमित करने–इसकी बुराइयों को कम करने या इसे पूरी तरह से दबाने में पूरी तरह से सक्षम

है। किसी नागरिक को इस प्रकार नशीली शराब खुदरा बेचने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है; यह राज्य के नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक का विशेषाधिकार नहीं है। चूंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें समुदाय को खतरा है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है या ऐसी शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है जो इसकी बुराइयों को चरम सीमा तक सीमित कर देगी। विनियमन का तरीका और सीमा शासी प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर है। वह प्राधिकार ऐसे अधिकारियों में निहित हो सकता है जो इसे आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदनों को पारित करने और उस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति उचित समझे। यह केवल विधायी इच्छा का मामला है।"

(48) उपरोक्त अंशों का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गयाः –

"इन टिप्पणियों में हमारी पूरी सहमति है और वे याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद को पूरी तरह से नकारात्मक करते हैं। विनियमन के प्रावधान इसके सभी विभिन्न क्षेत्रों में शराब के व्यापार को विनियमित करने का इरादा रखते हैं और वैध हैं।

अंत में, निष्कर्ष में, उनके आधिपत्य ने इस प्रकार कहाः –

"हमारी राय है कि यह तर्क कि विनियमन के प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ता के शराब व्यापार को स्वतंत्र रूप से चलाने के अधिकारों को कम करते हैं, कायम नहीं रखा जा सकता है।"

(49) इस सवाल पर कि क्या विधायिका, पूर्वी बंगाल और असम उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के हित में नियंत्रण और प्रतिबंध प्रदान कर सकती है, ने उनके आधिपत्य का ध्यान आकर्षित किया है। असम राज्य बनाम सृष्टिकर डोवेरेह और अन्य (10) में फिर से सुप्रीम कोर्ट की। उनका आधिपत्य इस प्रकार मनाया गयाः –

'धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम की प्रांतीय सरकार ने विस्तृत नियम बनाए हैं। नियमों का भाग IV लाइसेंस, निपटान और शुल्क, लाइसेंस की अवधि और संख्या, दुकानों का स्थान, स्थानीय जनता की राय का पता लगाना, निपटान की प्रक्रिया, कुछ

व्यक्तियों को खुदरा लाइसेंस देने पर रोक, लाइसेंस प्रदान करना आदि से संबंधित है। इत्यादि। अधिनियम और नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने का पूर्ण अधिकार नहीं है और अधिनियम और नियमों का उद्देश्य नशीली शराब की खपत को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है, ऐसा नियंत्रण और प्रतिबंध स्पष्ट रूप से आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता का संरक्षण, और राजस्व बढ़ाना।"

(50) जम्मू और कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 20 के तहत उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त को प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग पर विचार करते समय। 1958, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 19 (6) की तुलना में, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने कृष्ण कुमार नरूला बनाम जम्मू राज्य मामले में शराब की बिक्री पर लगाए गए विधायी प्रतिबंधों के प्रश्न की जांच की। और कश्मीर और अन्य (11)। यह मामला दो याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें उस अधिनियम की धारा 20

के तहत दिए गए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण का दावा किया गया था। उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त ने इस आधार पर उनके लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने उन इलाकों से स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया था, जहां उनकी दुकानें थीं, जैसा कि उन इलाकों के निवासियों से प्राप्त शिकायतों पर उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था। वहां पर दुकानें जारी रहने के विरोध में। याचिकाकर्ताओं को अन्यत्र स्थानांतरित होने से इनकार करने के कारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उन्हें अपनी पसंद के स्थानों पर शराब बेचने का व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है और परिणामस्वरूप उनके लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। . ऐसी बिक्री पर विनियमन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत शराब की बिक्री के संबंध में व्यवसाय को विनियमित करने की विधायी शक्ति पर विचार करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने निम्नानुसार कहाः –

"एक विधायिका किसी विशेष व्यापार या कारोबार पर प्रतिबंध लगा सकती है या यहां तक कि उसे प्रतिबंधित भी कर सकती है और न्यायालय, विशेष समय या स्थान पर उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध या निषेध को उचित ठहरा सकता है..." .....किसी भी अन्य वस्तु की तरह शराब भी बनाई, लाई या बेची जा सकती है। इसका सेवन दुनिया भर में किया जाता है, हालांकि कुछ देश आर्थिक या नैतिक आधार पर इसे प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करते हैं। किसी सौदे की नैतिकता या अन्यथा गतिविधि की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है, हालांकि यह उक्त गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकता है। किसी गतिविधि की अवैधता गतिविधि के चरित्र को प्रभावित नहीं करती बल्कि उस पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है। यदि कोई कानून शराब के लेन-देन पर रोक लगाता है, तो लेन-देन व्यवसाय नहीं रह जाता, बल्कि उक्त कानून उक्त लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है।"

"किसी नागरिक को जहां भी वह चाहे व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और उसका अधिकार सार्वजनिक सुविधा के

हित में कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा लगाए गए किसी भी उचित प्रतिबंध के अधीन होना चाहिए।"

(51) जैसा कि पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है, कूवरजी बी. भरुओहा के मामले (8) से प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, उनका आधिपत्य, अंत में इस प्रकार है: –

“इसलिए, हम मानते हैं कि शराब का व्यापार एक व्यवसाय है और एक नागरिक को उस वस्तु का व्यापार करने का अधिकार है; लेकिन राज्य जनहित में उक्त अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकता है।

(52) अधिनियम की धारा 36(जी) के प्रावधानों और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 7 द्वारा लगाया गया

प्रतिबंध मनमाना या अनुचित नहीं है। अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार 'इच्छा' पर लाइसेंस रद्द करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति पूर्ण शक्ति नहीं है। यह ओवर–राइडर के अधीन है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार रद्द करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लाइसेंस की शर्तें इस तरह के रद्दीकरण के लिए प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में, खंड (जी) के तहत एक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस में शामिल शर्त का पालन करने के लिए सहमत हो गया है कि उसका लाइसेंस उस खंड के तहत रद्द किया जा सकता है। शक्ति को मनमाने और अनियंत्रित के रूप में समाप्त किया जा सकता है, यदि अभिव्यक्ति के बाद, 'इच्छा पर', विधायिका ने आगे यह प्रावधान नहीं किया होता कि यह लाइसेंस की शर्तों के अधीन है जैसा कि लाइसेंसधारी और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत है। ऐसा प्रावधान करके, विधायिका ने अपनी इच्छानुसार शक्ति का प्रयोग करने और दुरुपयोग होने से बचने के लिए मनमानी या निरंकुश शक्ति के प्रयोग को प्रावधान से बाहर कर दिया है। नियमों के नियम 7 के अनुसार,

जिस अवधि के लिए वे लागू हैं, उसकी सीमा के बिना दिए गए लाइसेंस को शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द किया जा सकता है या एक वर्ष के नोटिस के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में लाइसेंस के निर्धारण के लिए आक्षेपित नोटिस उस नियम के पहले भाग के तहत लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए नहीं है, बल्कि उस नियम के दूसरे भाग के तहत इसका निर्धारण किया जा रहा है, नियम का वह भाग प्रदान करता है कि यदि लाइसेंस है वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाने की मांग की गई है जैसा कि अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के आधार पर वर्तमान मामले में किया जा रहा है, लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस की शर्त संख्या 9 विशेष रूप से कहती है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता–कंपनी को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि उसका लाइसेंस नोटिस की तारीख से कम से कम एक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाएगा। शर्त संख्या 9 में प्रतिवादी संख्या 2 पर लगाए गए वैधानिक दायित्व को पूरी तरह से शामिल किया गया है, जिसमें लाइसेंस में एक शर्त शामिल है कि

याचिकाकर्ता–कंपनी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बताए बिना किसी भी कारण बताए बिना अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए सहमत हो गई है जैसा कि खंड में प्रदान किया गया है (छ) अधिनियम की धारा 36 के नियमों के नियम 7 के अनुसार कम से कम एक वर्ष का नोटिस देने पर। विधायिका ने लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लाइसेंस के निर्धारण के लिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसे विवेकाधीन बनाने में प्रचुर सावधानी बरती है, यदि लाइसेंसधारक किसी एक शर्त पर सहमत हो और नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने लाइसेंस के निर्धारण के लिए एक नोटिस भी प्रदान किया है। यदि ऐसा निर्धारण कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नोटिस देने के बाद किया जाना है। याचिकाकर्ता कंपनी स्वयं शर्तों संख्या 9 के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के लिए सहमति से सहमत हुई। उसे उस शर्त के अनुसार नोटिस दिया गया है। शर्त संख्या 9 की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होने के बाद, जो अनुबंध की एक शर्त है, याचिकाकर्ता पलट कर यह नहीं कह सकता कि वह शर्त अनुचित है। यह याचिकाकर्ता–कंपनी की पसंद का परिणाम है। वह इसे केवल

इसलिए स्वीकार करने से नहीं बच सकता क्योंकि वह इसके विरुद्ध कठोरता से कार्य करेगा।

(53) इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अधिनियम की धारा 36(जी), नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध धारा 20(2) और 21(सी) के साथ असंगत हैं। और (डी) अधिनियम के. धारा 36(जी) कहती है कि यदि लाइसेंसधारी सहमत है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द कर सकता है। याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा शर्त संख्या 9 के अनुपालन के लिए किए गए समझौते को अधिनियम की धारा 36 (जी) द्वारा लगाया गया प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। यह शर्त लाइसेंस के मुख्य भाग में याचिकाकर्ता–कंपनी के सहमत होने के कारण मौजूद है, न कि प्रतिवादी संख्या 2> द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध लगाए गए किसी प्रतिबंध के कारण।

(54) अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 36(जी) और एक ओर शर्त संख्या 9 के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 7 और दूसरी ओर धारा 20(2) के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति है। और अधिनियम की अन्य धारा 20(2) पर 21(सी) और (डी) में प्रावधान है कि धारा के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन प्राधिकरण के अलावा किसी भी डिस्टिलरी का निर्माण या काम नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के 21. यह प्रावधान बताता है कि यह प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी लाइसेंस के अधिकार के तहत है कि याचिकाकर्ता–कंपनी डिस्टिलरी का निर्माण या काम कर सकती है और वह भी दिए गए लाइसेंस में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार। यह। इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता–कंपनी को लाइसेंस जारी किया ताकि उसे जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्माण और काम करने में सक्षम बनाया जा सके।

(55) जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियम 7 वित्तीय आयुक्त को लाइसेंस निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है और लाइसेंसधारी को एक अवधि के लिए नोटिस देने के बाद लाइसेंस निर्धारित करना अनिवार्य बनाकर उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। एक वर्ष से कम। यह धारा 36(जी) और नियम 7 के संदर्भ में है कि याचिकाकर्ता–कंपनी शर्त संख्या 9 पर सहमत हुई। चूंकि नियमों की धारा 36(जी) और नियम 7 का दायरा लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ा जाता है। दिखाता है, उनके और धारा 20(2) के बीच कोई असंगतता नहीं है। धारा 20(2) लाइसेंस देने की शक्ति से संबंधित है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद नियम 7 और शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ी गई धारा 36(जी) के संदर्भ में इसे रद्द करने का प्रश्न उठता है। . यह वैध रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली अधिनियम की धारा 20(2) किसी भी तरह से धारा 36(जी) के प्रावधानों और प्रतिवादी को सक्षम करने वाली शर्त संख्या 9 के साथ पढ़े गए नियम 7 के साथ

असंगत है। लाइसेंस निर्धारित करने के लिए नंबर 2. धारा 20(2) एक अलग विषय से संबंधित है और धारा 36(जी), नियम 7 और शर्त संख्या 9 द्वारा निपटाए गए विषय से स्वतंत्र है। इसी तरह, इस तर्क के लिए कोई वारंट नहीं है कि धारा 36 के बीच कोई असंगतता मौजूद है। (जी) अधिनियम और नियमों के नियम 7 को लाइसेंस की शर्त संख्या 9 और धारा 21 के खंड (सी) और (डी) के साथ पढ़ा जाए। अधिनियम की धारा 21 के खंड (सी) का विषय पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के विषय के समान हैः–

21(सी) "वित्तीय आयुक्त, ऐसे प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन, जो राज्य सरकार लगा सकती है, ...

(सी) किसी डिस्टिलरी या शराब की भट्ठी के निर्माण और कामकाज का लाइसेंस देना।"

(56) इस प्रकार, आपके पास अधिनियम की धारा 21(सी) की तुलना में अधिनियम की धारा 36(जी), नियमों के नियम 7 या लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के बीच कोई असंगति नहीं है। धारा 21 का खंड (डी) लाइसेंस देने, लाइसेंस दिए जाने की अवधि, स्प्रिट के निर्माण और अन्य मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 21 के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि नियम बनाने की शक्ति किसी भी तरह से धारा 36 (जी), नियम 7 या शर्त संख्या के प्रावधानों के विपरीत है। 9. अधिनियम की धारा 21 के खंड (डी) के अनुसरण में बनाए गए किसी भी नियम को यह दिखाने के लिए नहीं बताया गया है कि वह नियम किसी भी तरह से खंड (डी) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के विपरीत है। यह उस नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में है कि नियमों के नियम 7 को तैयार किया गया है और यह फिर से प्रतिवादी संख्या 2 में मौजूद शक्ति के अनुसरण में है कि याचिकाकर्ता–कंपनी को

कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नोटिस दिया गया है। . इस प्रकार, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अधिनियम की धारा 36(जी), नियमों के नियम 7 और लाइसेंस की शर्त संख्या 9 द्वारा लगाए गए कोई भी अनुचित प्रतिबंध हैं और ये धारा के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। अधिनियम के 20(2) और 21(सी) और (डी)।

(57) वर्तमान मामले में लाइसेंस को लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 36(जी) के तहत रद्द कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा उस धारा के खंड (ए) से (एफ) के तहत की गई किसी भी अनियमितता के कारण लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया है, बल्कि उस धारा के तहत लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विशेष रूप से इसके खंड (जी) के तहत। धारा 36 खंड (ए) से (जी) के तहत निर्दिष्ट विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित है जिसके तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिया गया लाइसेंस, परमिट या पास रद्द या निलंबित किया जा

सकता है। परिस्थितियों में से एक, जिसके तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बिना किसी कारण बताए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों में सहमत है, अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) में शामिल है। यह धारा 21 है, जो वित्तीय आयुक्त को सामान्य रूप से शक्ति प्रदान करती है। धारा 21(बी) के तहत, इसके पास अधिनियम की धारा 20(2) के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत शराब बनाने के लिए स्थापित किसी भी डिस्टिलरी को बंद करने की शक्ति है। नोटिस में लाइसेंस रद्द करने की सामान्य शक्ति का उल्लेख किया गया है, जो निस्संदेह प्रतिवादी संख्या 2 में निहित है और अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के अनुसरण में लाइसेंस में शामिल शर्त संख्या 9 का भी उल्लेख किया गया है। नियमों के नियम 7 का विशिष्ट उल्लेख, इसे केवल इसलिए दोषपूर्ण या अमान्य नहीं माना जा सकता क्योंकि नोटिस के मुख्य भाग में धारा 36(जी) का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। धारा 36 के खंड (जी) और नियमों के नियम 7 के अनुसरण में तैयार की गई शर्त संख्या 9 के संदर्भ में कोई संदेह नहीं है

कि नोटिस अधिनियम की धारा 36 के खंड (जी) के आधार पर दिया गया था। अधिनियम की धारा 21 में दिए गए लाइसेंस को रद्द करने की सामान्य और व्यापक शक्ति, यदि नियमों की धारा 21 (बी) शर्त संख्या 9 और नियम 7 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि रद्द करने का नोटिस दिया गया है। याचिकाकर्ता–कंपनी अधिनियम की धारा 36 के तहत, विशेष रूप से उस धारा के खंड (जी) के तहत।

` (58) इस प्रश्न पर विचार करने से पहले कि क्या याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से अनुरोध किया गया लाइसेंस, अधिनियम की धारा 41 के तहत रद्द किया जा सकता है, उस धारा की भाषा की जांच करना आवश्यक है। इसका प्रासंगिक भाग उपधारा (1) है। यह इस प्रकार चलता हैः–

“41(1) जब भी प्राधिकरण, जिसने इस अधिनियम के तहत लाइसेंस, परमिट या पास दिया है, यह मानता है कि ऐसे लाइसेंस, परमिट

या पास को धारा 36 में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से वापस ले लिया जाना चाहिए, तो वह बराबर राशि भेजने पर पन्द्रह दिनों के लिए उसके संबंध में देय फीस की राशि के लिए, या तो लाइसेंस वापस ले लिया.........

(ए) ऐसा करने के अपने इरादे के लिखित रूप में पंद्रह दिनों के नोटिस की समाप्ति पर, या

(बी) बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत।"

(59) जैसा कि उपरोक्त पुनरुत्पादित धारा 41 से पता चलता है, यह लाइसेंस के निर्धारण या रद्दीकरण के विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यह केवल लाइसेंस वापस लेने से संबंधित है। धारा 41 में यह भी प्रावधान है कि निकासी धारा 36 में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण या कारण से होनी चाहिए। इस प्रकार, यदि धारा 36 के किसी भी खंड के तहत लाइसेंस रद्द करने की मांग की जाती है, तो धारा 41 के प्रावधान(1) लागू नहीं होगा. वर्तमान मामले में, यह अधिनियम

की धारा 36 के खंड (जी) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदत्त शक्ति के आधार पर है, जिसे ग्रहणी की शर्त संख्या 9 के साथ पढ़ा जाता है कि इसके निर्धारण के लिए नोटिस दिया गया है। याचिकाकर्ता–कंपनी. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 36 (जी) के तहत रद्द किए जाने वाले लाइसेंस को रद्द करने के उद्देश्य से धारा 41 का संदर्भ पूरी तरह से गलत और अप्रासंगिक है। धारा 41 की भाषा एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है, जिसमें कार्य या व्यवसाय के संदर्भ में लाइसेंस जारी रखने पर विचार किया जा रहा है और फिर भी जहां तक लाइसेंसधारी का संबंध है, लाइसेंस लाइसेंसधारी से वापस ले लिया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता–कंपनी के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता–कंपनी का लाइसेंस तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिनियम की धारा 41 के तहत तथ्यहीन है।

(60) याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से पांचवां और आखिरी बिंदु यह है कि लाइसेंस के निर्धारण की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके

से और एक संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया है, जिससे लाइसेंस रद्द करना शून्य हो गया है।

(61) जैसा कि जनता द्वारा की गई शिकायतें और करनाल की नगरपालिका समिति और पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और याचिकाकर्ता–कंपनी और उत्तरदाताओं के बीच पारित पत्राचार के सर्वेक्षण से पता चलता है, 1939 से लेकर अब तक 1964 के अंत में लागू नोटिस की सेवा की तारीख, प्रतिवादी प्रयास कर रहे थे और बार–बार याचिकाकर्ता–कंपनी से संपर्क कर रहे थे ताकि डिस्टिलरी को करनाल शहर के मध्य में अपनी वर्तमान साइट से स्थानांतरित किया जा सके क्योंकि इसकी स्थिति उपद्रव का स्रोत थी और अपने इलाके के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा। याचिकाकर्ता–कंपनी ने जवाब में, इन परिस्थितियों में, किसी न किसी बहाने से डिस्टिलरी को उस साइट से अलग स्थान पर स्थानांतरित करने के अपने दायित्व को टाल दिया है। यह उनके द्वारा अपनाई गई टालमटोल की रणनीति का परिणाम है,

जैसा कि उस स्थान से डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के खिलाफ उनके द्वारा बताए गए कारणों से स्पष्ट है कि डिस्टिलरी वहीं बनी हुई है।

(62) बहुत पहले 1939 में, करनाल की नगर समिति ने उस इलाके के निवासियों की शिकायत पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें डिस्टिलरी की साइट स्थित है, कि उस स्थान पर डिस्टिलरी को बनाए रखना वांछनीय नहीं था। प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी को डिस्टिलरी को उस साइट से किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस में, याचिकाकर्ता–कंपनी को कहीं और अपनी डिस्टिलरी स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उत्तरदाताओं को 5J वर्ष जैसी लंबी अवधि देने में अत्यधिक लापरवाही बरती गई थी। उत्तरदाताओं द्वारा दिखाए गए आवास के प्रति उत्तरदायी होने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ उपयुक्त साइट की व्यवस्था करने और डिस्टिलरी का निर्माण शुरू करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। याचिकाकर्ता–कंपनी की इच्छा के

अनुसार, तीन साल का अतिरिक्त समय दिया गया और उसके बाद एक साल का और विस्तार दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रबंधन के प्रति बिना किसी दुर्भावना या दुर्भावना के न केवल चिंतित थे, बल्कि याचिकाकर्ता–कंपनी के लाइसेंस के निर्धारण के कठोर कदम से बचने के लिए बार–बार समय बढ़ा रहे थे। .

457

(63) 21 जनवरी 1949 को, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, अंबाला को एक और पत्र भेजा गया था, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता–कंपनी को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रबंधन को डिस्टिलरी को नगरपालिका सीमा से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए। करनाल के प्रबंधन द्वारा सुझाए गए किसी उपयुक्त स्थल पर। उस पत्र में यह भी बताया गया था कि याचिकाकर्ता–कंपनी को स्थानांतरित करने में विफलता के

परिणामस्वरूप दिए गए लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस 30 सितंबर, 1950 को समाप्त हो जाएगा और यदि याचिकाकर्ता–कंपनी स्थानांतरित नहीं हुई तो लाइसेंस निर्धारित माना जाएगा। उस नोटिस की समाप्ति से पहले. उस संचार के उत्तर में, याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा उत्तरदाताओं की मंजूरी के लिए करनाल शहर के नजदीक एक साइट का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि चयनित साइट भविष्य में आवासीय उद्देश्यों के लिए विकसित होने की संभावना वाले क्षेत्र में थी और यह याचिकाकर्ता–कंपनी को सुझाव दिया गया था कि करनाल के शहरी क्षेत्र के आसपास लगातार बढ़ती निर्माण गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, साइट करनाल की नगरपालिका सीमा से 10 मील से कम नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त स्थल की स्वयं व्यवस्था करने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी ने सुझाव दिया कि डिस्टिलरी स्थल के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा संबोधित 18 सितंबर 1952 के पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता–कंपनी को यह सूचित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या

1 ने याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करना उचित नहीं समझा और कंपनी को स्वयं कुछ उपयुक्त भूमि खरीदनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भूमि. याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा 1956 तक इस उद्देश्य के लिए किसी भी साइट को सुरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 23 जून, 1956 को, प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता–कंपनी को एक पत्र संबोधित किया कि उसे उपयुक्त साइट खरीदने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए और डिस्टलरी को वहां शिफ्ट करना। याचिकाकर्ता–कंपनी ने इन सभी सुझावों को अनसुना कर दिया।

(64) 1958 में, पंजाब विधान सभा के पटल पर चौधरी धर्म सिंह, एम.एल.ए. द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि जनता द्वारा बार–बार की गई शिकायतों के बावजूद, याचिकाकर्ता–कंपनी की डिस्टिलरी केंद्र में क्यों स्थित है? करनाल शहर का स्थानांतरण नहीं किया गया था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा मांग की गई कि करनाल की जनता और विशेष रूप से उस इलाके के निवासियों, जहां डिस्टिलरी का स्थान स्थित है, के लगातार चल रहे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, डिस्टिलरी को तुरंत स्थानांतरित

किया जाए। यहां तक कि पंजाब विधान सभा का प्रस्ताव भी डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए याचिकाकर्ता–कंपनी को स्थानांतरित करने में विफल रहा। 2 फरवरी, 1959 को विधानसभा द्वारा एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि करनाल शहर में डिस्टिलरी का अस्तित्व एक उपद्रव था और इसे बिना किसी देरी के अपने वर्तमान स्थान से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। करनाल नगरपालिका समिति के एक प्रस्ताव और विधानसभा के दो प्रस्तावों के बावजूद, याचिकाकर्ता कंपनी डिस्टिलरी को उसी स्थान पर बनाए रखने के अपने रुख पर अड़ी रही, जहां वह मौजूद थी। इससे विधानसभा में एक और सवाल खड़ा हो गया कि करनाल शहर से डिस्टिलरी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। सदन के पटल पर सरकार से इसे बिना समय गंवाए वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की गयी. इस प्रस्ताव का भी याचिकाकर्ता–कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और व्यर्थ चला गया। इन परिस्थितियों में, लाइसेंस की शर्त संख्या 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत याचिकाकर्ता–कंपनी को 5 मई,

1959 को नोटिस दिया गया था, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि उसका लाइसेंस 15 मई, 1960 को निर्धारित किया जाएगा। इस नोटिस का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता कंपनी ने 26 मई, 1959 को जवाब में प्रतिवादी नंबर 3 से तुच्छ और अप्रासंगिक पूछताछ की कि क्या डिस्टिलरी को एक उपयुक्त साइट पर स्थानांतरित करने से संबंधित स्थितियां भविष्य में विकसित होने की संभावना नहीं है। और इस्तेमाल की गई धुलाई के स्वच्छ निपटान के प्रावधान को हटा दिया गया है या अभी भी लागू किया गया है। हालाँकि प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता–कंपनी को 4 जुलाई, 1959 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि याचिकाकर्ता कंपनी को इन दो शर्तों का पालन करना होगा और उन्हें माफ नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता–कंपनी ने डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(65) नगरपालिका समिति और विधानसभा के प्रस्तावों का हवाला देते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्य डिस्टिलरी को उसके वर्तमान स्थल से किसी अन्य स्थान पर बिना किसी देरी के स्थानांतरित करने की सर्वोपरि आवश्यकता के लिए मुखर हैं। इसे स्थानांतरित करने के लिए

उत्तरदाताओं की मांग का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी अपनी वर्तमान साइट से डिस्टिलरी को हटाने के लिए उत्तरदाताओं की वैध मांग का विरोध करने और देरी करने के लिए टाल–मटोल कर रही है और बहाने बना रही है। यह याचिकाकर्ता कंपनी की टालमटोल की रणनीति है जिसने उसे अवांछनीय स्थल पर डिस्टिलरी के निरंतर अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

(66) डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी ने एक प्रस्ताव रखा कि याचिकाकर्ता–कंपनी के पास रोहतक जिले के गांव राठधना की नवीकरण संपत्ति में 181 एकड़ का क्षेत्र है और कंपनी डिस्टिलरी को वहां स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, बशर्ते कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र के अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 200 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के औचित्य के बारे में जाने बिना और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि रोहतक जिला, जिसमें राठधना गांव की संपत्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जाना था, एक क्षेत्र था,

जिसमें निषेध था लागू किया गया, डिस्टिलरी को याचिकाकर्ता–कंपनी को स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता के कारण कंपनी को लिखा गया कि रुपये की राशि। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक 2,76,000 रुपये जमा करने होंगे या यदि याचिकाकर्ता कंपनी उस राशि को जमा करने में सक्षम नहीं है या उस कीमत पर भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहती है, तो याचिकाकर्ता–कंपनी निजी बातचीत से भूमि की व्यवस्था कर सकती है। भूमि के अधिग्रहण के लिए सहमत होने और कलेक्टर के पुरस्कार द्वारा निर्धारित भूमि की कीमत के अधीन उक्त राशि जमा करने या फिर अपनी भूमि की व्यवस्था करने के बजाय, याचिकाकर्ता–कंपनी ने आपत्ति उठाई कि जैसा कि था माल की लोडिंग या अनलोडिंग के लिए राठधाना के रेलवे स्टेशन पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह आवश्यक होगा कि रेलवे प्रशासन के प्रतिवादी नंबर 1 की कीमत पर याचिकाकर्ता–कंपनी को रेलवे साइडिंग प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से सुझाए गए विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करने के बजाय, प्रतिवादी नंबर 1 या रेलवे

प्रशासन की कीमत पर रेलवे साइडिंग प्रदान करने की उचित दलील देकर उस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। जवाब में यह भी जोड़ा गया कि कीमत रु. 2,76,000, जो स्पष्ट रूप से अनुमानित था और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की कीमत का हिसाब–किताब का आंकड़ा अत्यधिक था। अपने विवेकपूर्ण उत्तर में, यह आगे सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र को 200 एकड़ से बढ़ाकर 400 एकड़ कर दिया जाए। याचिकाकर्ता–कंपनी की जमीन के इतने बड़े हिस्से के अधिग्रहण की यह मांग इस बात का संकेत है कि याचिकाकर्ता–कंपनी किस हद तक जवाबों में काल्पनिक शर्तें पेश कर रही है और असाधारण दावे कर रही है? उसका स्वयं का। यह सोचते हुए कि याचिकाकर्ता–कंपनी का मतलब व्यवसाय करना था, हालांकि गलती से, और अंततः स्थानांतरित हो सकता है, लाइसेंस के निर्धारण के लिए पहले नोटिस, जिसे 25 जनवरी, 1961 तक बढ़ा दिया गया था ताकि वह उस तारीख तक डिस्टिलरी को स्थानांतरित करने में सक्षम हो सके, को आगे तक के लिए स्थगित रखा गया था।

आदेश. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा मांगी गई पूछताछ के जवाब में कि क्या याचिकाकर्ता–कंपनी रेलवे साइडिंग के लिए किए जाने वाले खर्चों को चुकाने के लिए तैयार है, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 19 मई, 1961 द्वारा सूचित किया था कि कंपनी रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोई वित्तीय दायित्व वहन करने के लिए तैयार नहीं है और याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। यह देखते हुए कि नगरपालिका समिति और पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्तावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नगरपालिका समिति ने पंजाब के राज्यपाल को करनाल शहर से डिस्टिलरी को इस आधार पर हटाने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा कि इससे लोगों को परेशानी होगी। इसके इलाके के निवासी. रिपोर्ट के लिए अभ्यावेदन को स्वास्थ्य निदेशक को भेजा गया था। 16 जनवरी, 1962 को, निदेशक ने प्रतिवादी नंबर 3 को इस आशय की रिपोर्ट भेजी कि डिस्टिलरी इससे निकलने वाली अप्रिय गंध और घृणित गंध के कारण एक उपद्रव थी और करनाल शहर में इसका अस्तित्व उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। जो इसके

आसपास रहते थे. अंत में, उन्होंने सिफारिश की कि यह आवश्यक है कि इसे इसके वर्तमान स्थान से हटा दिया जाए। 19 अगस्त, 1963 को, प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता–कंपनी को सूचित किया कि लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस, जिसे स्थगित रखा गया था, को पुनर्जीवित किया गया था और याचिकाकर्ता–कंपनी को 31 मार्च, 1964 तक स्थानांतरित कर देना चाहिए, ऐसा न होने पर लाइसेंस निर्धारित होगा. जवाब में, 14 नवंबर, 1963 के पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता–कंपनी ने प्रतिवादी नंबर 2 से अनुरोध किया कि कंपनी 400 एकड़ से 60 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अपनी पिछली मांग को कम करने के लिए तैयार थी और इसके लिए बैंक की गारंटी देने के लिए तैयार थी। रु. उस क्षेत्र की कीमत के लिए 50,000 रुपये या नकद में जमा की जाने वाली भूमि की कीमत के बराबर राशि इस आकर्षक उपक्रम के साथ जमा करें कि डिस्टिलरी अधिग्रहित भूमि के कब्जे की तारीख से 60 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। और उस तारीख से 12 महीने के भीतर कारखाने का निर्माण पूरा हो जाएगा। याचिकाकर्ता–कंपनी ने

रुपये का चेक अग्रेषित किया। भूमि अधिग्रहण की कीमत के लिए 10 जनवरी, 1964 को रोहतक के कलेक्टर को लिखे पत्र के साथ 50,000 रु.

(67) याचिकाकर्ता–कंपनी ने 4 मई 1959 के नोटिस की वैधता को चुनौती दी, जिसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में 19 अगस्त 1963 को पुनर्जीवित किया गया था, इस आधार पर कि वह शर्त 9 के तहत एक साल के नोटिस को मंजूरी देने की हकदार थी। लाइसेंस और इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस के निर्धारण के लिए नोटिस, जिसके आधार पर प्रतिवादी नंबर 2 अपने लाइसेंस का निर्धारण करना चाहता था, 19 मार्च, 1964 को एक रिट याचिका दायर करके अवैध था। इसमें 1964 की सिविल रिट संख्या 472 दर्ज है। .नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध था. 5 मई, 1959 को इसकी तामील होने के बाद, यह 4 मई, 1960 से 19 अगस्त, 1963 तक निलंबित रहा और इस प्रकार एक स्पष्ट और निरंतर वर्ष के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। उत्तरदाताओं की ओर से यह देखने की चिंता कि डिस्टिलरी को उसके परिसर से स्थानांतरित कर दिया गया

है, ने याचिकाकर्ता–कंपनी के कहने पर उन्हें अधिग्रहण के लिए 14 अप्रैल, 1964 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया। गांव राठधना की जागीर में 60 एकड़ जमीन। अधिसूचना जारी होने के बाद 14 अप्रैल 1964 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 और 17(2) के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई। 1964 की सिविल रिट याचिका संख्या 472, जिसका शीर्षक करनाल डी डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड है। करनाल बनाम पंजाब पंजाब और अन्य राज्य (12), को 26 अक्टूबर 1964 को उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच, जिसमें फाल्शॉ सी.न्यायमूर्ति . और ग्रोवर न्यायमूर्ति . शामिल थे, ने यह कहते हुए अनुमति दे दी कि 19 अगस्त, 1963 को नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता–कंपनी का एक वर्ष से कम अवधि के लिए अस्तित्व में रहना अमान्य था और उसे रद्द कर दिया गया था। उप सचिव, राजस्व ने 29 अक्टूबर, 1964 को एक आदेश दर्ज किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री के साथ चर्चा के परिणामस्वरूप, यह

निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से अधिग्रहण करने की कोई बाध्यता नहीं थी। याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए भूमि, कि डिस्टिलरी को करनाल से किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, कि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और सरकार को याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रबंध निदेशक को सभी उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वह स्थानांतरित हो सके। आसवनी. फिर, याचिकाकर्ता–कंपनी के लाइसेंस के निर्धारण के लिए 14 दिसंबर, 1964 को नोटिस जारी किया गया। यह इस नोटिस की वैधता है, जिस पर याचिकाकर्ता–कंपनी ने आपत्ति जताई है।

461

(68) पार्टियों के बीच पारित पत्राचार की उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि यह याचिकाकर्ता कंपनी का प्रबंधन है, जो उत्तरदाताओं के साथ अन्याय कर रहा है और डिस्टिलरी के लिए उत्तरदाताओं की पूरी तरह से मांग का विरोध करने के लिए अतिरिक्त कारण बता रहा है। याचिकाकर्ता–कंपनी को उसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित किया

जा रहा है। यह याचिकाकर्ता–कंपनी का आचरण है जिसमें दुर्भावना की बू आती है और याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से सुझाए गए अनुसार उत्तरदाताओं को सद्भावना की कमी की दलील के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह जनता के हित में है कि याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा डिस्टिलरी को बिना किसी रोक–टोक या झिझक के अपनी वर्तमान साइट से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दुर्भावना की यह दलील वर्तमान रिट याचिका में बाद में सोचा गया है। यह दूसरे पैर पर है कि जूता चुभता है।

(69) याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से पेश हुए श्री अवस्थी ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी के कहने पर उन कार्यवाहियों को शुरू करने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही को छोड़ने

पर जोर दिया और कहा कि अधिग्रहण की कार्यवाही को त्यागने की प्रक्रिया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनाया गया उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावना का सूचक है। याचिकाकर्ता–कंपनी के कहने पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता कंपनी को पुरानी डिस्टिलरी के स्थान पर नई डिस्टिलरी बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 पर कोई वैधानिक या अन्यथा कोई दायित्व नहीं था। यह भोग का कार्य था या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिखाया गया एहसान था। यदि प्रतिवादी नंबर 1 ने इसे अनुचित समझा या अन्यथा याचिकाकर्ता–कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करना उचित नहीं समझा, तो दुर्भावना का अनुमान नहीं लगाया गया अनिवार्य रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही को बंद करने के अधिनियम से पालन करें। उत्तरदाताओं की ओर से अपने रिटर्न में एक ठोस कारण बताया गया है जिसके कारण उन कार्यवाहियों को रद्द करना आवश्यक हो गया। यह कहा गया है कि गांव राठधना की संपत्ति में जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वह रोहतक जिले में स्थित है और उस जिले में एक डिस्टिलरी के लिए भूमि

का अधिग्रहण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लागू की गई निर्धारित नीति के विपरीत होगा। शराबबंदी लागू करने के लिए उस जिले को सूखा रखना।

(70) करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य (12) मामले में उपरोक्त संदर्भित डिवीजन बेंच द्वारा न्यायिक रूप से यह देखा गया है कि यह डिस्टिलरी अपनी वर्तमान साइट पर एक उपद्रव है। डिवीजन बेंच ने इस प्रकार टिप्पणी कीः –

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिस्टिलरी, जो करनाल शहर में स्थित है, एक उपद्रव है और वर्षों से सरकार इसे शहर से दूर किसी स्थान पर हटाने की कोशिश कर रही है।"

(71) उसमें विशेष रूप से कहा गया है कि रिट याचिका में या याचिकाकर्ता–कंपनी के प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं के खिलाफ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

(72) निर्णय समाप्त करने से पहले, हम उल्लेख कर सकते हैं कि बहस के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि सरकार का इरादा याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय को रोकने का नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि डिस्टिलरी को बिना किसी अनुचित देरी के वर्तमान स्थल से किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किया जाता है तो सरकार लाइसेंस देने के लिए तैयार होगी। यह फिर से आसवनी को अन्यत्र स्थानांतरित करने में सरकार की सद्भावना को दर्शाता है।

(73) परिणामस्वरूप, रिट याचिका अस्वीकार कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

के.एस.के.

(1) ए.आई.आर. 1969 म.प्र. 176. _

(2) 1970 (1) एस.सी.डब्ल्यू.आर. 194

(3) 1970 (1) एस.सी.डब्ल्यू.आर. 713. 441

(4) आई.एल.आर. (1970) द्वितीय पृ. और घंटा 772.

(5) ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 40.

(6) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 150।

(7) ए.आई.आर., 1963 एस.सी., 1811।

(8) ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 220. 448

(9) (1890) 34 कानून संस्करण 620,

(10) ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 414. 450

(11) ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1368.

(12) 1965 पी.एल.आर. 144.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा